www.dhyeyaias.com

दिसम्बर 2020 | अंक 03

PERFECT 7

साप्ताहिक समसामयिकी

ध्येय IAS की एक नई पहल

1 भारत का विद्युत वाहन बाजार

लक्ष्य-2030

2 भारत की कोविड-19 परीक्षण और अनुरेखण रणनीतियाँ : सामंजस्य की आवश्यकता

3 केन-बेतवा लिंक परियोजना से संबंधित मुद्दे

4 CAATSA और तुर्की की S-400 डील : भारत की चिंताएँ

5 बड़े उद्यमियों के हाथों में बैंकिंग सेक्टर : एक अवलोकन

6 कृषि का व्यवसायिकरण : एक नया दृष्टिकोण

7 विकास और समृद्धि के लिए पूर्वोत्तर राज्यों से समुचित जुड़ाव की आवश्यकता

ध्येयIAS®
most trusted since 2003

ध्येय IAS : एक परिचय

विनय कुमार सिंह
संस्थापक एवं सी.ई.ओ.

हम इस मंत्र में विश्वास रखते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अद्वितीय है; प्रत्येक व्यक्ति निपुण है एवं प्रत्येक व्यक्ति में असीमित क्षमता है। ध्येय IAS हमेशा से आत्मप्रेरणादायक मार्गदर्शन को प्रोत्साहित करता रहा है जिससे कि छात्रों के भीतर ज्ञान का सृजन हो सके। शिक्षा प्रदान करने का उद्देश्य ज्ञान के सृजन, प्रसार एवं अनुप्रयोग को एकीकृत रूप में पिरोकर एक सह-क्रियाशील प्रभाव उत्पन्न करना है। ध्येय IAS हमेशा से ही छात्रों के भीतर मानवीय मूल्यों एवं सत्यनिष्ठा को विकसित करने का पक्षधर रहा है जिससे कि उनमें निर्णय लेने की क्षमता का विकास हो और वे एक ऐसी परिस्थिति का सृजन करें जो न सिर्फ उनके लिए बल्कि समाज, राष्ट्र और विश्व के लिए भी बेहतर हो। ध्येय IAS नये और प्रभावशाली तरीकों से अपने इस मिशन को पूरा करने के लिए प्रत्येक छात्र को हर प्रयास में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। इसके लिए हम निरंतर और निर्बाध रूप से अपने अध्ययन कार्यक्रम और शिक्षण पद्धतियों में परिवर्तन एवं परिमार्जन करते रहते हैं।

सिविल सेवा परीक्षा का पाठ्यक्रम प्रतियोगी छात्रों में केवल ज्ञान के प्रति जुनून ही नहीं उत्पन्न करता है बल्कि यथार्थ जीवन में उसका प्रयोग भी सिखाता है। ध्येय IAS प्रतियोगी छात्रों के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करता है साथ ही उनमें ईमानदारी एवं सत्यनिष्ठा जैसे मूल्यों का भी सृजन करता है।

क्यू. एच. खान
प्रबंध निदेशक

ध्येय IAS एक ऐसा संस्थान है जिसका लक्ष्य हमेशा से ही छात्रों के समग्र विकास का रहा है। हमारे संस्थान के शिक्षक अपने-अपने विषय के विशेषज्ञ होते हैं जिससे कि छात्रों को प्रत्येक विषय में अधिकतम मदद प्राप्त हो सके। यह एक ऐसा बहुमुखी संस्थान है जहाँ छात्रों को उच्चस्तरीय कक्षाओं और समृद्धशाली अध्ययन सामग्री के साथ-साथ हरसंभव सहायता उपलब्ध करायी जाती है।

आज ध्येय IAS सिविल सेवा परीक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी पहचान रखता है, क्योंकि हम उच्चस्तरीय एवं गुणवत्तापूर्ण प्रदर्शन में विश्वास रखते हैं। हम छात्रों को ज्ञान की परिधि बढ़ाने के लिए निरंतर प्रोत्साहित करते रहते हैं ताकि वे पाठ्यक्रम के दायरे से सदैव दो कदम आगे रहें। हमारा मुख्य उद्देश्य छात्रों को उनकी आन्तरिक क्षमता का बोध कराना होता है जिससे कि वे अपनी एक अलग पहचान बनाकर कल के समाज का कीर्तिमान बन सकें।

Perfect 7 : एक परिचय

कुरबान अली
मुख्य संपादक

मैं उत्साहपूर्वक यह बताना चाहता हूँ कि 'Perfect 7' का नया स्वरूप छात्रों एवं पाठकों के लिए और अधिक जानकारियों को एक अत्यंत आकर्षक स्वरूप में लेकर सामने आ रहा है। इस कार्य के लिए संपादकीय दल को मेरी सुभेच्छा। शुरूआत से ही ध्येय IAS द्वारा रचित 'Perfect 7' को पाठकों का बेहद प्रेम और स्नेह मिलता रहा है। किसी भी संस्था का नाम एवं प्रसिद्धि उसके छात्रों एवं शिक्षकों की दक्षता एवं उपलब्धियों पर निर्भर करती है। एक शिक्षक का मुख्य कार्य उसके छात्रों की क्षमताओं का निर्माण कर उसे सफलता के मार्ग पर अग्रसर करना होता है, उसी क्रम में यह पत्रिका इस संस्थान की शक्तियों का प्रदर्शन करते हुए उसके छात्रों एवं पाठकों में समसामयिकी मुद्दों पर एक व्यापक दृष्टिकोण को विकसित करने के लक्ष्य को लेकर प्रकाशित की जा रही है जिसके द्वारा विभिन्न प्रबुद्ध शिक्षकों, लेखकों एवं छात्रों को एक मंच पर सम्मिलित किया जा रहा है, ताकि वे अपने नवाचार युक्त विचारों को एक दूसरे के साथ साझा कर सकें।

इस क्रम में किये जा रहे कठिन परिश्रम को मेरी हार्दिक शुभकामनाएँ।

आशुतोष सिंह
प्रबंध संपादक

हमने अपनी साप्ताहिक पत्रिका का ना केवल नाम 'Perfect 7' रखा है, बल्कि उसे 'परफेक्ट' बनाने के लिए हर संभव प्रयास भी किया है। यह सर्वविदित है कि किसी कार्य की शुरूआत सबसे चुनौतीपूर्ण होती है और सबसे महत्वपूर्ण भी। इसलिए यह स्थिति हमारे सामने भी आयी।

हमारे लिए यह चुनौती और भी बड़ी इसलिए साबित हुई क्योंकि हमने अपनी पत्रिका की गुणवत्ता के लिए अत्यधिक उच्च मानक तय किया। हमने शुरूआत में ही तय कर लिया था कि हम पत्रिका के नाम पर प्रतिभागियों को 'सूचनाओं का कचरा' नहीं प्रदान करेंगे। हमने यह निश्चय किया कि सिविल सेवा की परीक्षा को केंद्र में रखते हुए, हम उन्हें 'Perfect 7' के रूप में वह रामबाण देंगे जो सीधे लक्ष्य को भेदेगा। इसके लिए हमने 'मल्टी फिल्टर' और 'सिक्स सिगमा' प्रणाली को अपनाया जिसके तहत अलग-अलग स्तरों पर चर्चा कर अंततः उन विषयों और मुद्दों को इसमें समाहित किया जाता है जहाँ से परीक्षा में प्रश्नों का पूछा जाना अधिसंभाव्य है।

इसके अतिरिक्त प्रत्येक स्तर पर गलतियों को दूर कर 'Perfect 7' को त्रुटिहीन, प्रवाहपूर्ण और आकर्षक रूप से आपके सामने लाया जाता है। गुणवत्तापूर्ण सामग्री देने के अतिरिक्त, समयबद्ध रूप से इसको आपके समक्ष लाना भी हमारे लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि यह एक साप्ताहिक पत्रिका है। हमें इस बात का बेहद हर्ष एवं गर्व है कि पहले अंक से लेकर इस अंक तक कोई भी सप्ताह ऐसा नहीं रहा जब 'Perfect 7' अपने तय समय पर प्रकाशित न हुई हो।

'Perfect 7' का यह जो नया संस्करण हम आपके सामने ला रहे हैं, इसमें हमारे परिश्रम से कहीं ज्यादा आपके प्रेम और स्नेह की भूमिका है जिसकी वजह से हम बिना रूके, बिना थके प्रत्येक सप्ताह आपके लिए यह पत्रिका प्रकाशित करते हैं। आपकी शुभकामनाओं से यह क्रम आगे भी जारी रहेगा।

प्रस्तावना

हमने **'PERFECT 7'** पत्रिका को सिविल सेवा परीक्षा के प्रतियोगी छात्रों को ध्यान में रखकर बनाया है। सिविल सेवा की दृष्टि से महत्वपूर्ण राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का चयन कर **'PERFECT 7'** में सात महत्वपूर्ण मुद्दों एवं खबरों का संकलन किया जाता है। इसके अतिरिक्त सात ब्रेन बूस्टर्स, सात महत्वपूर्ण तथ्य, पीआईबी के सात महत्वपूर्ण बिंदुओं एवं सात महत्वपूर्ण ग्राफिक्स के माध्यम से संकल्पनाओं का समावेशन **'PERFECT 7'** को सिविल सेवा परीक्षा के लिए 'गागर में सागर' साबित करता है।

'PERFECT 7' के सात महत्वपूर्ण मुद्दों का संकलन करते समय उन मुद्दों के पक्ष, विपक्ष, विशेषताओं तथा उनसे भारत एवं विश्व पर पड़ने वाले प्रभावों की समीक्षा प्रस्तुत की जाती है, ताकि छात्र उन मुद्दों के बारे में एक समझ विकसित कर सकें। **'PERFECT 7'** के सात महत्वपूर्ण खबरों के जरिए छात्रों को सिविल सेवा की दृष्टि से महत्वपूर्ण विषयों की जानकारी उपलब्ध करायी जाती है। इस पत्रिका के सात महत्वपूर्ण तथ्यों एवं पीआईबी के सात महत्वपूर्ण बिंदुओं के जरिए हम अपने छात्रों को अतिरिक्त जानकारी उपलब्ध कराते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य सिविल सेवा परीक्षा के सभी पहलुओं को समाहित करना है। **'PERFECT 7'** के सात ब्रेन बूस्टर्स के जरिए समसामयिक विषयों की जानकारी संक्षेप में एवं आकर्षक रूप में प्रस्तुत की जाती है जिससे कि छात्रों द्वारा इसे सरलता से आत्मसात किया जा सके। इसके अतिरिक्त इस पत्रिका में अभ्यास प्रश्नों का समावेशन छात्रों को सिविल सेवा परीक्षा के लिए स्वयं का मूल्यांकन करने में सहायता प्रदान करता है। अन्य पत्रिकाओं की भांति हम छात्रों को केवल सतही जानकारी उपलब्ध कराने में विश्वास नहीं रखते बल्कि सारगर्भित बहुपक्षीय और त्रुटिरहित जानकारी प्रदान करने का अथक प्रयास करते हैं जिससे सिविल सेवा में हमारे छात्र सफलता अर्जित कर सकें, क्योंकि छात्रों की सफलता ही हमारी पत्रिका की कसौटी है। हमने अपने अथक प्रयास एवं परिश्रम के जरिए **'PERFECT 7'** पत्रिका को 'परफेक्ट' बनाने का कार्य किया है, फिर भी यदि कोई त्रुटि रह गयी हो तो उसे सुधारने में आपके सुझाव सादर आमंत्रित हैं।

जीत सिंह
सम्पादक, ध्येय **IAS**

संघ लोक सेवा आयोग व अन्य राज्य लोक सेवा आयोगों द्वारा प्रारम्भिक व मुख्य परीक्षा में विगत कुछ वर्षों से राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से संबंधित प्रश्नों की संख्या में बढ़ोत्तरी हुई है। इसकी पुष्टि विगत वर्षों में संपन्न हुई परीक्षाओं के प्रश्न पत्र से की जा सकती है। इसलिए हमने **'PERFECT 7'** पत्रिका के माध्यम से उन मुद्दों एवं खबरों का संकलन किया है, जो परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। **'PERFECT 7'** पत्रिका न केवल प्रारम्भिक व मुख्य परीक्षा के लिए उपयोगी है, बल्कि यह साक्षात्कार के लिए भी अत्यंत उपयोगी है। इसमें समसामयिक घटनाओं को बेहद रोचक ढंग से तालिका,फ्लोचार्ट एवं चित्रों के माध्यम से समझाया गया है। **'PERFECT 7'** के सात महत्वपूर्ण मुद्दों को संकलित करते समय हमारा प्रयास न केवल उन मुद्दों के सभी पहलुओं अर्थात् एक स्पष्ट विश्लेषणात्मक सांचे में ढालने का रहा है बल्कि ऐसे मुद्दों का इसमें विस्तृत विवेचन भी किया गया है, जिनका अन्य समसामयिक पत्रिकाओं में जिक्र तक नहीं होता है। **'PERFECT 7'** के सात ब्रेन बूस्टर्स के माध्यम से समसामयिक विषयों की जानकारी को बेहद सटीकता व आकर्षक रूप से प्रस्तुत किया गया है, जिससे छात्रों को कम समय में भी उपयोगी जानकारी सुलभ हो सके। इसके अतिरिक्त **'PERFECT 7'** पत्रिका में सात महत्वपूर्ण खबरें, सात महत्वपूर्ण पीआईबी, सात महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न व सात महत्वपूर्ण तथ्यों का समावेश भी किया गया है। इस पत्रिका में अभ्यास प्रश्नों का समावेशन छात्रों को सिविल सेवा परीक्षा के लिए स्वयं का मूल्यांकन करने में सहायता प्रदान करता है। यहाँ यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि किसी भी पत्रिका में तथ्यों की मात्रा से ज्यादा महत्वपूर्ण उसकी गुणवत्ता होती है, इसलिए इसी सिद्धांत का अनुपालन करके हमने सारगर्भित रूप में यह पत्रिका आपके सम्मुख प्रस्तुत की है, चूंकि कोई भी कृति अंतिम नहीं होती है, उसमें सुधार की सदैव संभावनाएँ विद्यमान रहती हैं। अतः सभी छात्रों से अनुरोध है कि अपने बहुमूल्य सुझावों व समालोचनाओं से हमें अवगत कराएं।

अवनीश पाण्डेय
सम्पादक, ध्येय **IAS**

ध्येय IAS
most trusted since 2003

www.dhyeyaias.com

PERFECT 7

साप्ताहिक समसामयिकी

ध्येय IAS की एक नई पहल

दिसम्बर 2020 | अंक 03

ध्येय टीम

संस्थापक एवं सी.ई.ओ.	➢ विनय कुमार सिंह
प्रबंध निदेशक	➢ क्यू. एच. खान
मुख्य संपादक	➢ कुरबान अली
प्रबंध संपादक	➢ आशुतोष सिंह
संपादक	➢ जीत सिंह ➢ अवनीश पाण्डेय ➢ ओमवीर सिंह चौधरी ➢ रजत झिंगन
संपादकीय सहयोग	➢ प्रो. आर. कुमार
मुख्य लेखक	➢ अजय सिंह ➢ अहमद अली ➢ स्वाती यादव ➢ स्नेहा तिवारी
लेखक	➢ अशरफ अली ➢ गिरराज सिंह ➢ हरिओम सिंह ➢ अंशुमान तिवारी
समीक्षक	➢ रंजीत सिंह ➢ रामयश अग्निहोत्री
आवरण सज्जा एवं विकास	➢ संजीव कुमार झा ➢ पुनीश जैन
विज्ञापन एवं प्रोन्नति	➢ गुफरान खान ➢ राहुल कुमार
प्रारूपक	➢ कृष्ण कुमार ➢ कृष्णकांत मंडल ➢ मुकुन्द पटेल
कार्यालय सहायक	➢ हरीराम ➢ राजू यादव

Content Office

ध्येय IAS
most trusted since 2003

DHYEYA IAS
302, A-10/11, Bhandari House,
Near Chawla Restaurants,
Dr. Mukherjee Nagar,
Delhi-110009

विषय सूची

7 महत्वपूर्ण मुद्दे एवं उन पर आधारित विषयनिष्ठ प्रश्न 01–15

- भारत का विद्युत वाहन बाजार : लक्ष्य-2030
- भारत की कोविड-19 परीक्षण और अनुरेखण रणनीतियाँ : सामंजस्य की आवश्यकता
- केन-बेतवा लिंक परियोजना से संबंधित मुद्दे
- CAATSA और तुर्की की S-400 डील : भारत की चिंताएँ
- बड़े उद्यमियों के हाथों में बैंकिंग सेक्टर : एक अवलोकन
- कृषि का व्यवसायिकरण : एक नया दृष्टिकोण
- विकास और समृद्धि के लिए पूर्वोत्तर राज्यों से समुचित जुड़ाव की आवश्यकता

7 महत्वपूर्ण ब्रेन बूस्टर्स 16–22

7 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर (ब्रेन बूस्टर्स पर आधारित) 23–24

7 महत्वपूर्ण खबरें 25–31

7 महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न (मुख्य परीक्षा हेतु) 32

7 महत्वपूर्ण तथ्य (प्रारंभिक परीक्षा हेतु) 33

7 महत्वपूर्ण उक्तियाँ (निबंध एवं उत्तर लेखन के लिए उपयोगी) 34

OUR OTHER INITIATIVES

UDAAN TIMES
Putting You Ahead of Time...
Hindi & English
Current Affairs
Monthly
News Paper

DHYEYA TV
Current Affairs Programmes hosted
by Mr. Qurban Ali
(Ex. Editor Rajya Sabha, TV) & by Team Dhyeya IAS
(Broadcasted on YouTube & Dhyeya-TV)

7 महत्वपूर्ण मुद्दे

01 भारत का विद्युत वाहन बाजार : लक्ष्य–2030

चर्चा का कारण

- सीईईडब्ल्यू सेंटर फॉर एनर्जी फाइनेंस द्वारा किये गये एक अध्ययन के अनुसार मार्च 2020 के अंत तक भारत में पंजीकृत ईवी की कुल संख्या केवल पांच लाख थी। अध्ययन के अनुसार, सभी वाहन खंडों में कुल ईवी बिक्री 2030 तक 10 करोड़ से अधिक हो सकती है, जो बाजार के मौजूदा आकार का 200 गुना होगी।
- भारत यदि इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी-EV) 2030 के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त करता है तो उसका ईवी बाजार करीब 14.42 लाख करोड़ रुपये का हो सकता है। हालांकि, इसके लिये उसे लगभग 12.50 लाख करोड़ रुपये के निवेश की आवश्यकता होगी।
- ध्यातव्य है कि इलेक्ट्रिक वाहन उत्सर्जन में कटौती और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करने में मदद करके दुनिया भर में जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

रिपोर्ट की मुख्य बातें

- अध्ययन में कहा गया है कि भारत की ईवी महत्त्वाकांक्षा को साकार करने के लिये वित्त वर्ष 2030 तक 158 गीगावॉट की अनुमानित वार्षिक बैटरी क्षमता की आवश्यकता होगी। इससे घरेलू निर्माताओं के लिये बड़े पैमाने पर बाजार में अवसर उपलब्ध होंगे।
- अध्ययन में नीति आयोग के लक्ष्य का हवाला देते हुए कहा गया कि भारत के ईवी 2030 लक्ष्य के अनुसार, 2030 तक सभी वाणिज्यिक कारों की 70 प्रतिशत, निजी कारों की 30 प्रतिशत, बसों की 40 प्रतिशत और दोपहिया व तिपहिया वाहनों की 80 प्रतिशत बिक्री ईवी की होगी।
- इलेक्ट्रिक वाहनों के लिये लगातार नीतिगत समर्थन भी महत्वपूर्ण होगा।
- अध्ययन में कहा गया कि भारत को वित्त वर्ष 2030 तक घरों में स्थित निजी चार्जिंग प्वाइंट के अतिरिक्त 29 लाख से अधिक सार्वजनिक चार्जिंग प्वाइंट की जरूरत होगी।

इलेक्ट्रिक वाहन

- एक इलेक्ट्रिक वाहन वह है जो एक आंतरिक-दहन इंजन के बजाय एक इलेक्ट्रिक मोटर पर संचालित होता है जो ईंधन और गैसों के मिश्रण को जलाकर बिजली उत्पन्न करता है।
- इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) में सड़क और रेल वाहन, सतह और पानी के नीचे के जहाज, इलेक्ट्रिक विमान और इलेक्ट्रिक अंतरिक्ष यान शामिल हैं।
- हालांकि इलेक्ट्रिक वाहनों की अवधारणा लंबे समय से रही है, लेकिन पिछले एक दशक में कार्बन फुटप्रिंट और ईंधन आधारित वाहनों के अन्य पर्यावरणीय प्रभावों के बीच इसके प्रति काफी रुचि बढ़ी है।
- इलेक्ट्रिक वाहनों को मोटे तौर पर 8 विभिन्न प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है–

- प्लग-इन इलेक्ट्रिक वाहन
- ऑन और ऑफ-रोड इलेक्ट्रिक वाहन
- अंतरिक्ष रोवर वाहन
- सीबॉर्न इलेक्ट्रिक वाहन
- एयरबोर्न इलेक्ट्रिक वाहन
- विद्युत संचालित अंतरिक्ष यान
- रेंज-विस्तारित इलेक्ट्रिक वाहन
- रेलबॉर्न इलेक्ट्रिक वाहन

इलेक्ट्रिक वाहनों के लाभ

- इलेक्ट्रिक कार (या इलेक्ट्रिक वाहन, ईवी) के पारंपरिक आंतरिक दहन इंजन कारों की तुलना में कई पर्यावरणीय लाभ हैं।
- ईवी ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने की क्षमता रखते हैं साथ ही भारत में इनके उपयोग से पेट्रोलियम पर निर्भरता भी कम हो सकती है।
- इसके अलावा वायु प्रदूषण से स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव को भी कम करने में भी ईवी सहायक हो सकता है।
- आधिकारिक आंकड़े बतातें हैं कि भारत अपने महत्त्वाकांक्षी इलेक्ट्रिक वाहन नीति के जरिए 2030 तक रोड और परिवहन से ही करीब 64 फीसदी ऊर्जा बचा सकता है और साथ ही करीब 37 फीसदी कार्बन का उत्सर्जन भी कम कर सकता है। इसके साथ ही करीब 60 बिलियन डॉलर भी 2030 तक बचाए जा सकते हैं।
- अक्षय उर्जा का प्रयोग करके ही कम कार्बन पैदा किया जा सकता है और यह इलेक्ट्रिक व्हीकल के जरिए ही संभव है।

इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए सरकारी योजनाएं और पहल

- फरवरी 2019 में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने FAME-II योजना के तहत 10,000 करोड़ रुपये के कार्यक्रम को मंजूरी दी। यह योजना 1 अप्रैल, 2019 से लागू हुई। इस योजना का मुख्य उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर तेजी से प्रोत्साहन और ईवी के लिए आवश्यक चार्जिंग बुनियादी ढांचे की स्थापना करके इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है।
- 2017 में, परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने 2030 तक 100 प्रतिशत इलेक्ट्रिक कारों को स्थानांतरित करने के भारत के इरादे को दर्शाते हुए एक बयान दिया। हालांकि, ऑटोमोबाइल उद्योग ने इस तरह की योजना के क्रियान्वयन पर चिंता जताई। सरकार ने बाद में इस योजना को 100 प्रतिशत से 30 प्रतिशत कर दिया।
- 2013 में, भारत ने राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान (NEMMP) 2020 का अनावरण किया, ताकि इलेक्ट्रिक वाहनों हेतु एक बड़ा परिवर्तन लाया जा सके और राष्ट्रीय ऊर्जा सुरक्षा, वाहनों के प्रदूषण और घरेलू विनिर्माण क्षमताओं के विकास के मुद्दों का समाधान किया जा सके। यह योजना सब्सिडी देने और ई-वाहनों के लिए सहायक आधारभूत संरचना तैयार करने के लिए थी।

रोजगार और आर्थिक विकास पर इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रभाव

- कच्चे तेल के आयात पर खर्च होने वाली कुल राशि की तुलना में भारत में बैटरी निर्माण उद्योग बड़ा हो सकता है। इससे भारतीय अर्थव्यवस्था को भारी बढ़ावा मिलेगा।
- मिनी और माइक्रो ऑटो कंपोनेंट उद्योगों को रखने के लिए एक सावधानीपूर्वक योजना बनाने की जरूरत है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग काम करते हैं। इनमें से कई कंपनियाँ वर्तमान में चालित नहीं हैं क्योंकि इलेक्ट्रिक वाहन अब पेट्रोल/डीजल वाहनों की जगह ले रहे हैं। इसलिए ईवी घटकों के निर्माण के लिए संक्रमण चरण के दौरान उनकी मदद करना भी अनिवार्य है।
- यूरोपीय जलवायु फाउंडेशन ने अनुमान लगाया है कि अधिक कुशल इलेक्ट्रिक कारों द्वारा तेल की मांग को कम करके, 2030 तक रोजगार 5,00,000 से 8,50,000 तक बढ़ जाएगा और सरकारों के लिए तेल क्षेत्र पर लगाये करों से होने वाली राजस्व हानि को अन्य आर्थिक क्षेत्रों में उच्च कर राजस्व द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकता है।
- ईवीएस बिजली, भंडारण और कई अन्य क्षेत्रों के लिए मजबूत और हल्के थर्माप्लास्टिक की उच्च मांग में अवसर पैदा करेगा।
- विश्व स्तर पर, इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री 2008 में 2000 से अधिक इकाइयों को बेची जा रही थी, जो 2017 में 10 लाख से अधिक हो गई थी। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव चीन में देखने को मिला, जहां पूरी दुनियां के 40 फीसदी से ज्यादा ईवी वाहन बिके जो अमेरिका की बिक्री के दोगुने से भी ज्यादा है।
- इलेक्ट्रिक कारों का भारतीय बाजार में हिस्सा 0.06 प्रतिशत है। सोसाइटी ऑफ मैन्युफैक्चरर्स ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (एसएमईवी) के अनुसार, 2017-18 में उत्तर प्रदेश लगभग 6878 इकाइयों की उच्चतम ईवी बिक्री के साथ राज्यों की सूची में सबसे ऊपर है, इसके बाद हरियाणा में 6,307 और गुजरात में 6,010 इलेक्ट्रिक वाहन हैं। महाराष्ट्र ने लगभग 4,865 ईवी इकाइयों की बिक्री की सूचना दी, जबकि पश्चिम बंगाल 4,706 इकाइयों की बिक्री के साथ पांचवें स्थान पर आया।

भारत को चाहिए स्पष्ट नीति

- ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का कहना है कि ईवी को लेकर जिस तरह से भारत का महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य है उसके लिए हमें एक स्पष्ट रूपरेखा बनानी होगी। बिजली वाहन अनिवार्य है लेकिन इनको लेकर सरकारी नीतियां बिलकुल स्पष्ट होनी चाहिए। सरकारी अधिकारी भी इस बात को स्वीकार करतें हैं कि ईवी की सफलता के लिए अनुदान, सब्सिडी, और स्पष्ट कानूनों का होना बहुत जरूरी है।
- लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या भारत की इतनी क्षमता है कि वह चीन की तरह के बाजार के निर्माण में सहयोग कर सके।
- रणनीतिक सहयोग और बाजार की जरूरतों के बीच सहयोग रहना बहुत जरूरी है। भारत को चीजें कुछ अलग ढंग से करनी होंगी, भारत को अपना बाजार विकसित करना होगा, चाहे सब्सिडी बहुत कम या फिर बिलकुल भी न हो। भारत अपने विशाल बाजार और सरकारी बेड़े में ईवी के प्रयोग से काफी फायदा उठा सकता है।

- क्योंकि भारत का इलेक्ट्रिक रास्ता दुनिया से थोड़ा अलग है, जहां दुनिया के विकसित बाजार कार केंद्रित हैं, वहीं भारत का रास्ता इससे अलग है। भारत की विजय रणनीति सब्सिडी और नवीनता के साथ इस बात में भी छुपी है कि वह किस तरह सार्वजिक परिवहन, जैसे बस, मेट्रो फीडर बस, शेयर गाड़ियां, स्कूल बस, डिलिवरी वाहनों को ईवी परिवहन के साथ जोड़ता है। इसके बाद दूसरे नंबर पर टू-व्हीलर को ईवी में विकसित करना होगा क्योंकि टू-व्हीलर ही सबसे ज्यादा प्रदूषण फैलाते हैं।
- एक्सपर्ट कहते हैं कि भारत के लिए जहां वाहनों की एवरेज स्पीड कम है और लोग कम ही दूरी का सफर करते हैं, साथ ही सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट का भी ज्यादा इस्तेमाल होता है, वहां यही रणनीति सबसे ज्यादा कारगर है। हालांकि सवाल विशाल निवेश का भी है क्योंकि इलेक्ट्रिक बसों और स्टैंडर्स बसों के निर्माण में काफी खर्चा आता है।

भारत में ईवी के लिए चुनौतियां

- देश में गहराई तक जड़ें जमा चुके दहन इंजन की जगह पर इलेक्ट्रिक ट्रेन इंजन का आना एक बड़ा परिवर्तन है। भारत को ईवी बाजार में बढ़त बनाने के लिए ग्राहकों का विश्वास जीतना बहुत जरूरी है। पावर और परफॉर्मेंस के नजरिए से देखें तो ज्यादातर इलेक्ट्रिक मॉडल उपभोगताओं की जरूरतों पर खरे नहीं उतर रहे हैं। ग्राहकों के सामने प्रमुख दिक्कत है रेंज की कमी, चार्जिंग की दिक्कत, बैट्री बदलने की दिक्कत और फिर ईवी का महंगा होना। इसके साथ ही ईवी के सामने फाइनेंस की भी दिक्कत है।
- इसके अलावा भारत के सामने दूसरी सबसे बड़ी चुनौती है बैट्री की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए उसके निर्माण हेतु जरूरी कच्चे सामान पर बढ़ती निर्भरता भारत को लीथियम, मैग्निशियम, कोबॉल्ट, निकेल और ग्रेफाइट जैसी धातुएं जो बैट्री निर्माण में जरूरी हैं, इनको आयात करना पड़ेगा, यानि बैट्री निर्माण के 40 फीसदी माल को आयात करना पड़ेगा। बैट्री के लिए जरूरी ये चीजें पर्याप्त रूप से चीन, लैटिन अमेरिका और अफ्रीका में पाई जाती हैं।
- इसके अलावा एसी बनाम डीसी चार्जिंग स्टेशनों, ग्रिड स्थिरता और श्रेणी की चिंता पर स्पष्टता की कमी अन्य कारक हैं जो ईवी उद्योग के विकास में बाधा है।

निष्कर्ष

- वैश्विक ऑटोमोबाइल, जैविक ईंधन को पीछे छोड़कर आगे बढ़ रहा है। भारत ने भी इस ओर अपनी अभिरूचि दिखाई है लेकिन उसके पास न तो स्पष्ट नीति है और न ही कार्य-प्रणाली। हालांकि भारत इस व्यापार में नेतृत्व कर सकता है, लेकिन इसके लिए उसे इलेक्ट्रिक वाहन को सस्ता करने की रणनीति बनानी होगी।
- साफ है कि शून्य उत्सर्जन हासिल करने के लिए कई स्तरों पर एक साथ काम करना होगा। भारत में कई बाधाएं हैं। हालाँकि वह उन्नत बाजारों से पीछे नहीं रहेगा जो पहले ही इस तरफ काफी बढ़त बना चुके हैं। लेकिन इसके लिए भारत को अविष्कारशील होना होगा ताकि ईवी वाहन सस्ते हों। इसमें जीत हासिल करने और साफ पर्यावरण के लिए उसे इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट को शेयर्ड मोबिलिटी और जन परिवहन से भी जोड़ना होगा।

सामान्य अध्ययन पेपर-3

Topic:
- बुनियादी ढांचाः ऊर्जा, बंदरगाह, सड़क, विमानपत्तन, रेलवे आदि।

Topic:
- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी-विकास एवं अनुप्रयोग और रोजमर्रा के जीवन पर इसका प्रभाव।

प्र. इलेक्ट्रिक वाहन लक्ष्य 2030 को प्राप्त करने के लिए भारत का ईवी बाजार कितना तैयार है? आलोचनात्मक व्याख्या करें।

02 भारत की कोविड-19 परीक्षण और अनुरेखण रणनीतियाँ : सामंजस्य की आवश्यकता

चर्चा का कारण

- हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस से देश के सबसे बुरी तरह प्रभावित राज्यों से कहा है कि वो टेस्टिंग और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग को शीर्ष प्राथमिकता दें।

वर्तमान स्थिति

- भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगभग 1 करोड़ हो गई है।
- हालाँकि सक्रिय मामलों की संख्या लगातार घट रहे हैं।
- परन्तु अभी भी भारत के सामने कम लागत में ज्यादा से ज्यादा प्रभावी टेस्टिंग करने की चुनौती है, हालांकि रिसर्चर्स कोरोना टेस्ट के लिए और भी किट्स तैयार कर रहे हैं और भारत में भी कोरोना की टेस्टिंग के लिए कई तरह की किट्स यूज हो रही हैं।

कोरोना से संबंधित टेस्ट

1. RT-PCR

- पूरी दुनिया में कोरोना टेस्ट करने के लिए सबसे ज्यादा RT-PCR का यूज हो रहा है। इसका फुल फॉर्म Reverse transcription-polymerase chain reaction है।
- विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (ICMR) ने RT-PCR को टेस्टिंग का 'गोल्ड स्टैंडर्ड' बताया है।
- इस टेस्ट में DNA को 'एममिब फाई' किया जाता है ताकि उसे एनालाइज किया जा सके। इसके बाद सैंपल को PCR मशीन में रखा जाता है जो हीटिंग और कूलिंग के अलग-अलग साइकलों के जरिए टारगेट DNA की करोड़ों कॉपी बनाती है। फिर इसमें एक डाई मिलाई जाती है, अगर सैंपल पॉजिटिव है तो डाई चमकने लगती है। लैब के भीतर यह टेस्ट लगभग 100% सटीक है। हालांकि सैंपल कलेक्शन से लेकर रिजल्ट आने तक में 24 घंटे या उससे ज्याादा भी लग सकते हैं।

2. CT स्कैन

- चीन में इसका खूब इस्तेमाल हुआ। कोविड-19 की वजह से होने वाली 'लंग ऑपेसिटी' का स्कैन में पता चल जाता है। वुहान में RT-PCR में पॉजिटिव मिले 97% मरीजों के CT स्कैन में निमोनिया के लक्षण दिखे। हालांकि कई और स्टडी कहती हैं कि CT स्कैन से बड़ी संख्या में रोगियों का पता नहीं लगाया जा सकता।

3. LAMP

- यह PCR के सिद्धांत पर ही काम करता है। दोनों की टारगेट के जेनेटिक मैटीरियल को एम्प्लिफाई करते हैं। PCR में जहां कूलिंग और हीटिंग के लिए खास इक्विपमेंट यूज होता है, वहीं LAMP की टेस्टिंग मशीनरी छोटी होती है। इससे सिर्फ एक घंटे में नतीजे आ जाते हैं और टेस्टिंग के लिए ट्रेन्ड टेक्नीशियंस की जरूरत भी नहीं है। हालांकि इस टेस्ट का ज्यादा इस्तेमाल नहीं हुआ है।

4. रेपिड ऐंटीबॉडी टेस्ट

- एंटीबॉडी टेस्ट कोविड-19 का पता लगाने वाले टेस्ट से अलग है और यह नहीं बताएगा कि, आप संक्रमित हैं या नहीं।
- जब आप किसी वायरस के संपर्क में आते हैं तो आपका शरीर ब्लड और टिश्यू में रहने वाली एंटीबॉडीज बनाने लगता है। ये एंटीबॉडीज प्रोटीन होते हैं, जो वायरस को शरीर में फैलने से रोकते हैं। टेस्ट के जरिए यह पता लगाया जाता है कि शरीर इन्हें बना रहा है या नहीं। अगर यह मौजूद हैं तो यह संभावना बढ़ जाती है कि आप कोविड-19 के संपर्क में आ चुके हैं।

5. रेपिड ऐंटीजेन टेस्ट

- इस टेस्ट में उन प्रोटीन्स को डिटेक्ट किया जाता है जो वायरल का हिस्सा होती हैं। नाक या गले से सैंपल लेकर ऐंटीजेन टेस्टस मिनटों में रिजल्ट दे सकता है, मगर RT-PCR जितना सटीक नहीं है। हालांकि इस टेस्ट को अस्पतालों और कार्यालयों में लोगों को स्क्रीन करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। 15 जून को ICMR ने देश की पहली ऐंटीजेन टेस्टिंग किट को मंजूरी दी थी।

6. जीन एडिटिंग

- कुछ रिसर्चर्स CRISPR नाम के एक जीन-एडिटिंग टूल का इस्तेमाल कर सैंपल्स में वायरस के जेनेटिक सीक्वेंस का पता लगा रहे हैं। यह तरीका जीका के अलावा और भी वायरस के लिए पहले यूज हो चुका है

भारत में कोरोना टेस्टिंग वर्तमान स्थिति

- वर्तमान में भारत पीसीआर टेस्ट का इस्तेमाल कर रहा है लेकिन इस वक्त सिर्फ 60 फीसद टेस्ट इस पद्धति से किए जा रहे हैं। कई राज्य जो अपनी स्वास्थ्य नीतियों के लिए खुद जिम्मेदार हैं वो रैपिड एंटीजन टेस्ट (आरएटी) का इस्तेमाल करने लगे हैं, RAT से जांच तेजी से होती है, लेकिन इसके नतीजे RT-PCR की तुलना में कम भरोसेमंद होते हैं।
- माना जाता है कि फॉल्स निगेटिव (जहां संक्रमित लोगों की पहचान नहीं हो पाती) की वजह से आरएटी टेस्ट 50 फीसद नतीजे गलत दे देता है, हालांकि कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि ये टेस्ट वायरस हॉटस्पॉट वाले इलाकों में उपयोगी हो सकते हैं और सिर्फ भारत ही इस टेस्ट का इस्तेमाल नहीं कर रहा है, बल्कि लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण से जूझ रहे कुछ यूरोपीय देश भी रैपिड टेस्टिंग करने लगे हैं।

देश में कोरोना परीक्षण की विविधता का प्रभाव

- देश में महाराष्ट्र सर्वाधिक प्रभावित राज्य है। यहां देश के कुल मामलों में से 17 प्रतिशत मामले हैं।
- महाराष्ट्र की तुलना में कम आबादी वाले कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल में कोरोना वायरस के सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं।
- परन्तु कुल मामलों की संख्या के लिहाज से उत्तर प्रदेश और बिहार अधिक जनसंख्या के विपरीत बेहतर प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। यहां देश के क्रमशः 2.9 प्रतिशत और 1.6 प्रतिशत मामले ही प्रदर्शित हुए हैं, हालांकि, इसके पीछे टेस्टिंग का तरीका भी देखने की जरूरत है।

- टेस्टिंग के आंकड़े बताते हैं कि बिहार और उत्तर प्रदेश (और कुछ दूसरे राज्य) में कुल टेस्ट में से 50 फीसद से भी कम पीसीआर टेस्ट से हो रहे हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि कई मामलों की पहचान नहीं हो पा रही है। इसकी तुलना में महाराष्ट्र में लगभग 60 प्रतिशत RT-PCR टेस्ट होते हैं। हालांकि, अब सरकार राजधानी मुंबई में RAT की संख्या लगातार बढ़ा रही है।
- इसके अलावा तमिलनाडु राज्य में पूरी तरह से आरटी-पीसीआर टेस्ट हुए हैं, जो संक्रमण के विस्तार की ज्यादा साफ तस्वीर पेश करते हैं अर्थात वहां संक्रमण के प्रसार का सबसे सही परिणाम मिल रहा है।

राज्यों में कोरोना परीक्षण में विविधता का प्रभाव

- कोरोना संक्रमण काल में ऐसा देखने को मिला है कि राज्य अपने ज्यादा आबादी वाले इलाकों में पर्याप्त टेस्टिंग नहीं कर रहे हैं, जहां संक्रमण की दर कहीं ज्यादा हो सकती है।
- अभी हाल ही में 30 नवंबर तक के आंकड़ों से पता चलता है कि राजधानी लखनऊ में उत्तर प्रदेश के 13 प्रतिशत मामले हैं, परन्तु यहां राज्य के कुल टेस्ट में से 6 प्रतिशत से भी कम टेस्ट हुए हैं।
- वहीं राज्य में कानपुर जिले में दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा मामले दर्ज किए गए, लेकिन राज्य में हुए कुल टेस्ट में से तीन फीसद से भी कम कानपुर में हुए थे।
- इसके अलावा बिहार में भी जिला स्तर के डेटा में ऐसा ही ट्रेंड दिखता है। सबसे घनी आबादी वाले इलाकों में से एक, पटना में कुल मामलों में से 18 फीसद मामले सामने आए। जबकि राज्य के कुल टेस्ट में से सिर्फ तीन फीसद टेस्ट पटना में हुए थे।
- राज्य के दूसरे हिस्सों में इसकी तुलना में ज्यादा टेस्ट हुए, लेकिन मामलों की संख्या अपेक्षाकृत कम रही,क्योंकि जिन इलाकों में ज्यादा मामले हैं, अगर आप वहां कम टेस्ट करेंगे और कम मामलों वाले इलाके में ज्यादा टेस्ट करेंगे तो टेस्टिंग तो ज्यादा दिखेगी लेकिन मामले कम दर्ज होंगे।

बदलती निगरानी प्रणालियां

- भारत की कोविड-19 पर राष्ट्रीय गाइडलाइन कहती है कि राज्यों को कम से कम 80 फीसद पॉजिटिव मामलों के कॉन्टैक्ट 72 घंटे के अंदर ट्रेस कर लेने चाहिए। साथ ही स्वास्थ्य और परिवार कल्याण पर भारत की संसदीय समिति ने भी कहा है कि खराब कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और कम टेस्टिंग कोविड के घातक रूप से बढ़ने की एक वजह हो सकती है, परन्तु कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग पर हर राज्य से विश्वसनीय जानकारी हासिल करना मुश्किल है, क्योंकि सर्विलांस को लेकर राज्यों की तरफ से ठोस जानकारी का भी अभाव है।
- हालाँकि हाल में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 'हाई-रिस्क कॉन्टेक्ट की जल्द और सिस्टमेटिक ट्रैकिंग करने के लिए' उत्तर प्रदेश की तारीफ की थी।
- इसके अलावा केरल का डेटा बताता है कि चार मई से अब तक सामने आए सभी मामलों में संक्रमित लोगों के 95 फीसद प्राइमरी और सेकेंड्री कॉन्टैक्ट का पता लगा लिया गया।
- परन्तु इसके विपरीत, कर्नाटक के आंकड़ों से पता चलता है कि सितंबर से प्राइमरी और सेकेंड्री कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की संख्या वहां कम हुई है वहीं तेलंगाना राज्य के पास कोविड-19 की चपेट में आए लोगों के प्राइमरी और सेकेंड्री कॉन्टैक्ट के टेस्ट के अनुपात का डेटा मौजूद है।
- लेकिन किसी भी डेटासेट से ये पता नहीं चला कि क्या राष्ट्रीय गाइडलाइन के तहत दी गई समयावधि के अंदर संक्रमित व्यक्ति के 80 फीसद कॉन्टैक्ट का पता लगाया गया या नहीं और कई राज्य ये डेटा सार्वजनिक भी नहीं करते हैं।

क्या होता है कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग?

- कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का उद्देश्य होता है लोगों को जागरूक करना ताकि वे किसी कोरोना संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में ना पहुंचें और इस तरह से खुद भी इस वायरस को फैलाने से बचें। जानकार मानते हैं कि कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग बेहद अहम है।
- अगर यह ठीक से किया जाए तो सुनिश्चित किया जा सकता है कि दोबारा कभी लॉकडाउन की कोई जरूरत नहीं रहेगी। लेकिन यह कहने में जितना आसान है, करने में उतना ही मुश्किल।
- किसी व्यक्ति के कोरोना पॉजिटिव टेस्ट करने के बाद कॉन्टैक्ट ट्रेसर उससे संपर्क करता है और पता लगाता है कि वह कहां गया और किन लोगों के आसपास रहा। ट्रेसर उन लोगों पर ध्यान देता है जो आम तौर पर व्यक्ति के इर्दगिर्द रहते हैं, जैसे कि घर या दफ्तर में या फिर जो लोग छह फीट से कम दूरी में व्यक्ति के आसपास रहे, वह भी कम से कम दस मिनट तक।
- इन लोगों को फिर सेल्फ आइसोलेट करने को कहा जाता है। इन लोगों को लक्षणों पर ध्यान देने को कहा जाता है और जरूरत पड़ने पर इनका टेस्ट भी किया जाता है।

निष्कर्ष

- हालाँकि भारत में संक्रमण के रोजाना आ रहे मामलों में सितंबर के मध्य से कमी आई है, लेकिन इस बात की चिंता जताई जा रही है कि अलग-अलग टेस्टिंग रणनीति बीमारी के खिलाफ लड़ाई में बाधा बन सकती, इसलिए केंद्र और राज्य को इस चुनौती से साथ मिलकर लड़ना होगा।

सामान्य अध्ययन पेपर-2

Topic:

- स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधनों से संबंधित सामाजिक क्षेत्र/ सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित मुद्दे।

प्र. कोरोना वायरस टेस्ट और ट्रेसिंग रणनीति भारत में कोविड-19 से लड़ने में किस हद तक कारगर है? चर्चा करें।

03 केन–बेतवा लिंक परियोजना से संबंधित मुद्दे

चर्चा का कारण

- भारत की पहली नदी जोड़ो परियोजना के तहत केन-बेतवा लिंक के दूसरे चरण में बांध बनने की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। हालांकि पर्यावरण मंत्रालय इसको लेकर कुछ असहज है।
- इसी संदर्भ में पर्यावरण मंत्रालय के एक विशेषज्ञ पैनल ने केन-बेतवा नदी इंटरलिंकिंग परियोजना के अंतर्गत ओर नदी (Orr river) में बनाए जाने वाले बांध के लिए पर्यावरण मंजूरी को स्थगित कर दिया है। साथ ही पैनल ने इस परियोजना से जुड़े आंकड़ों को नए सिरे से पेश करने को कहा है, ताकि इससे पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव का अनुमान लगाया जा सके। इसी आधार पर तय किया जाएगा कि आगे जन सुनवाई की जरूरत है या नहीं।

पृष्ठभूमि

- गौरतलब है कि ओर नदी (Orr river) में बनने वाला बांध राष्ट्रीय परियोजना के रूप में पहचानी जाने वाली केन-बेतवा इंटरलिंकिंग परियोजना का हिस्सा है। केन-बेतबा लिंक परियोजना के दूसरे चरण में 40 मीटर ऊंचा और 2,218 मीटर लंबा बांध प्रस्तावित है। यह बांध मध्यप्रदेश के दिदौनी गांव में बनने वाला है। इससे मध्यप्रदेश के 90,000 हेक्टेयर में खेतों की सिंचाई हो सकेगी।
- इस परियोजना पर 30.65 अरब रुपए खर्च का अनुमान है। इसके लिए 3,730 हेक्टेयर जमीन चाहिए जिसमें 968.24 हेक्टेयर जंगल की जमीन भी शामिल है। परियोजना पूरी होने के बाद 2,723.70 हेक्टेयर जमीन डूब क्षेत्र में आ सकती है। इसमें सात गांव पूरी तरह और पांच गांव आंशिक रूप से डूब सकते हैं।
- इस परियोजना को 29 अक्टूबर, 2020 को मंत्रालय की विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (ईएसी) की अनुमति मिलने की उम्मीद थी।
- फरवरी 2016 में पहली बार इस परियोजना का मूल्यांकन किया गया था। मई 2016 में ईएसी ने पर्यावरण संबंधी मंजूरी के लिए इसकी अनुशंसा की थी। हालांकि, परियोजना में जंगल की जमीन भी शामिल है इसलिए

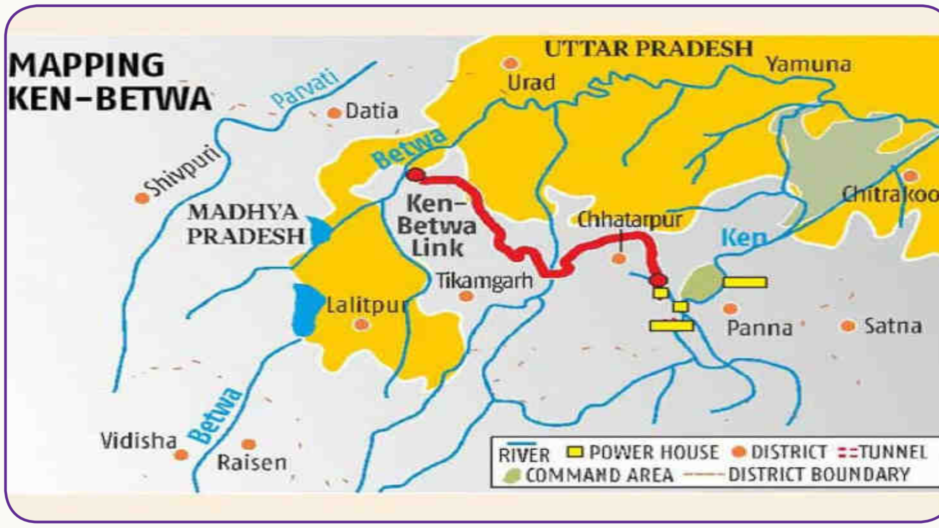

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने मध्य प्रदेश सरकार को राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी और वन विभाग से भी अनुमति लेने को कहा था।

- वर्ष 2019 में वन विभाग की अनुमति मिलने के बाद परियोजना को अक्टूबर 2020 में पर्यावरण संबंधी मंजूरी के लिए पेश किया गया।
- परन्तु पर्यावरण प्रभाव आंकलन के नियमों के अनुसार किसी भी परियोजना के निर्माण में पर्यावरण मंजूरी प्रदान करने के लिए जिस डाटा का उपयोग किया जाता है वह 18 माह के अधिक पुराना नहीं होना चाहिए।
- ओर बांध के मामले में जिन आंकड़ों के आधार पर पर्यावरण मंजूरी दी गयी है वे आंकड़े 18 माह से अधिक पुराने थे। इसलिए विशेषज्ञ पैनल ने केन-बेतवा नदी इंटरलिंकिंग परियोजना के अंतर्गत ओर नदी (Orr river) में बनाए जाने वाले बांध के लिए पर्यावरण मंजूरी को स्थगित कर दिया है।

क्या है केन-बेतवा नदी इंटरलिंकिंग परियोजना?

- सूखे से प्रभावित बुन्देलखण्ड इलाके में सिंचाई और पीने के लिये पानी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बहु-प्रतीक्षित केन-बेतवा नदी जोड़ो परियोजना का कार्यान्वयन केन्द्र सरकार द्वारा किया जा रहा है।
- यह परियोजना पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में तैयार की गई तीस प्रमुख नदियों को जोड़ने वाली 'नदी जोड़ो योजना' का ही हिस्सा है।
- केन नदी मध्य प्रदेश स्थित कैमूर की पहाड़ी से निकलती है और 427 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद उत्तर प्रदेश के बांदा में यमुना में मिल जाती है। वहीं बेतवा मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से निकलती है और 576 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में यमुना में मिल जाती है।
- केन-बेतवा नदी जोड़ो परियोजना के पूरा होने पर मध्य प्रदेश के छतरपुर, टीकमगढ़ और पन्ना जिले के 3.96 लाख हेक्टेयर और उत्तर प्रदेश के महोबा, बांदा और झाँसी जिले के 2.65 लाख हेक्टेयर हिस्से पर सिंचाई की व्यवस्था उपलब्ध हो सकेगी।
- ये सभी जिले बुन्देलखण्ड के सूखा प्रभावित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इस परियोजना के तहत केन नदी का अतिरिक्त पानी 230 किलोमीटर लम्बी नहर के माध्यम से बेतवा नदी में डाला जाना है।

केन-बेतवा नदी इंटरलिंकिंग परियोजना से जुड़े पूर्व विवाद

- विशेषज्ञ समिति द्वारा इस परियोजना को स्थगित किया जाना अचंभित करने वाली बात नहीं है क्योंकि केन-बेतवा नदी इंटरलिंकिंग परियोजना अपनी शुरूआत से ही विवादास्पद रही है।

- विवाद की मुख्य वजह मध्य प्रदेश द्वारा योजना के दोनों चरणों को एक साथ जोड़े जाने की माँग और उत्तर प्रदेश द्वारा गैर वर्षा काल यानि रबी की फसल के लिये अधिक जल की माँग थी।
- मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच नदियों को जोड़ने के लिये हुए पुराने समझौते के मुताबिक मध्य प्रदेश को 2650 मिलियन क्यूबिक मीटर (एमसीएम) और उत्तर प्रदेश को 1700 एमसीएम पानी दिया जाना था।
- वर्ष 2005 में उत्तर प्रदेश को रबी फसल के लिए 547 एमसीएम और खरीफ फसल के लिए 1153 एमसीएम पानी देना तय हो गया था। लेकिन वर्ष 2018 में उत्तर प्रदेश की मांग पर रबी फसल के लिए 700 एमसीएम पानी देने पर सहमति बन गई थी। केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश को 788 एमसीएम पानी देना तय कर दिया था। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने जुलाई 2019 में 930 एमसीएम पानी मांग लिया था, जिसे मध्य प्रदेश ने इंकार कर दिया था।
- मध्य प्रदेश ने पानी की जरूरतों का उल्लेख करते हुए कहा है कि रबी के सीजन में उत्तर प्रदेश को रबी 700 एमसीएम और खरीफ में 1000 एमसीएम पानी ही दिया जा सकेगा। इससे ज्यादा पानी देने पर मध्य प्रदेश में 4.47 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की मुश्किलें आएंगी।
- केन-बेतवा नदियों को जोड़ने के सन्दर्भ में एक अन्य मुख्य आपत्ति पन्ना टाइगर रिजर्व का 5500 हेक्टेयर से ज्यादा हिस्से का योजना क्षेत्र के अंतर्गत आना था। लेकिन नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ (national board for wild life) ने सशर्त इस पर अपनी सहमति दे दी है।

क्या है 'नदी जोड़ो योजना'?

- नदियों को आपस में जोड़ा जाना पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की एक महत्त्वाकांक्षी योजना थी। इस योजना में हिमालय से निकलने वाली 16 नदियों और प्रायद्वीप क्षेत्र से उद्गम वाली 14 नदियों को शामिल किया गया है। नदियों को आपस में जोड़ने संबंधी कार्यबल (टीएफ-आईएलआर) का गठन किया है।
- देश में जल और खाद्य सुरक्षा बढ़ाने के लिए नदी जोड़ने का कार्यक्रम काफी महत्वपूर्ण है और इससे जल की कमी, सूखा प्रभावित और वर्षा पर निर्भर कृषि क्षेत्रों में जल उपलब्ध कराने में सहायता मिलेगी।
- नदी जोड़ो योजना के तहत संबंधित राज्यों की सहमति के आधार पर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने हेतु चार प्राथमिक संपर्को जैसे केन-बेतवा संपर्क परियोजना (केबीएलपी) चरण-I और II, दमनगंगा-पिंजाल संपर्क, पार-तापी-नर्मदा संपर्क और महानदी-गोदावरी संपर्क की पहचान की गई थी।
- केन-बेतवा चरण-I और II, दमन-गंगा-पिंजाल संपर्क, पार-तापी-नर्मदा की डीपीआर तैयार करते हुए इसे संबंधित राज्यों के साथ साझा किया गया था।
- इसके साथ ही कावेरी-वैगई-गुंडार, दमनगंगा-पिंजाल और पार-तापी-नर्मदा जैसी नदी जोड़ परियोजनाओं के अलावा गोदावरी नदी के पानी को कावेरी बेसन की तरफ मोड़ने के वैकल्पिक प्रस्ताव, मानस-संकोश-तीस्ता-गंगा नदी जोड़ परियोजना और पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को पार्वती-कालीसिंध-चंबल नदी परियोजना के साथ जोड़ने पर भी सरकार के द्वारा कार्य किया जा रहा है।

निष्कर्ष

- हालाँकि केन-बेतवा लिंक परियोजना के लिए ज्यादातर स्वीकृतियां हासिल कर ली गई हैं और मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश के साथ डीपीआर साझा कर दी गई है। परन्तु उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच पानी की कमी वाले मौसम में जल की साझेदारी पर सहमति जैसे कुछ छोटे फैसले लंबित हैं और ऐसा अनुमान है कि परामर्श और सहयोग से इनका समाधान निकाल लिया जाएगा।
- इसी प्रकार, पार-तापी-नर्मदा लिंक परियोजना में जल की साझेदारी पर भी विचार चल रहा है। केन्द्रीय मंत्री ने नदियों को जोड़ने के कार्यक्रम को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए सभी सदस्यों विशेष रूप से संबंधित राज्य सरकारों से सहयोग और सहयता की अपील की।

आगे की राह

- इस परियोजना का उद्देश्य है सिंचाई की सुविधा बढ़ाना और खेती को समृद्ध कर गरीबी दूर करना। इसलिए अनिश्चित वर्षा की प्रवृत्ति और पानी के कम होते बहाव को ध्यान में रखते हुए योजनाकारों को किसानों को पुराने कृषि परंपरा पर लौटने और पुरानी फसलों के चयन के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए।
- चेक डैम का निर्माण व मिट्टी और जल संरक्षण के अन्य उपायों के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ऐसे में बिना नुकसान न सिर्फ क्षेत्र को हरा-भरा किया जा सकता है बल्कि इस दृष्टिकोण से कम लागत में ही कृषि समृद्ध होगी।

सामान्य अध्ययन पेपर-2

Topic:

- सरकारी नीतियों और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप और उनके अभिकल्पन तथा कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न मुद्दे।

सामान्य अध्ययन पेपर-3

Topic:

- संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण, पर्यावरण प्रभाव का आकलन।

प्र. केन-बेतवा लिंक परियोजना के परिप्रेक्ष्य में नदी-जोड़ो परियोजना की प्रासंगिकता पर विस्तार से चर्चा करें।

04 CAATSA और तुर्की की S-400 डील : भारत की चिंताएँ

चर्चा का कारण

- हाल ही में अमेरिका ने रूस से S-400 वायु रक्षा प्रणालियों की खरीद को लेकर तुर्की पर प्रतिबंध लगा दिया है। तुर्की नाटो समूह का पहला ऐसा देश है जिसके विरुद्ध काटसा कानून का प्रयोग किया गया है। गौरतलब है कि अमेरिका ने पिछले वर्ष F-35 जेट कार्यक्रम से तुर्की को बाहर कर दिया था। इसके साथ ही अमेरिका ने भारत समेत उन देशों को भी आगाह किया है, जो एस-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली खरीदने के इच्छुक हैं। अगले साल की शुरुआत में एस -400 एयर डिफेंस सिस्टम की खेप भारत को मिलने वाली है ,इसके मद्देनजर भारत,अमेरिका की चाल को करीब से देख रहा है। हालांकि भारत को S-400 वायु रक्षा प्रणाली पर निवर्तमान ट्रम्प प्रशासन से छूट मिली है। भारत को उम्मीद है कि आने वाले समय में बिडेन प्रशासन ट्रम्प के निर्णय को उलटने की दिशा में काम नहीं करेगा।

S-400 वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली क्या है?

- इसका पूरा नाम S-400 ट्रायम्फ (TRIUMF) है, जिसे नाटो देशों में SA-21 ग्रोलर (SA-21 GROWLER) के नाम से जाना जाता है। इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम को दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार माना जाता है। रूस द्वारा विकसित यह मिसाइल सिस्टम जमीन से हवा में मार करने में सक्षम है। एस-400 दुश्मन के हवाई हमलों को नाकाम करने में भी सक्षम है। इसके लॉन्चर से 48N6 सीरीज की मिसाइलें लॉन्च की जा सकती हैं। इसे अमेरिका के थाड (TERMINAL HIGH ALTITUDE AREA DEFENSE SYSTEM -THAAD) सिस्टम से बेहतर माना जाता है।
- यह मिसाइल सिस्टम 30 किमी तक की ऊँचाई पर एयरक्राफ्ट, क्रूज मिसाइल को नष्ट कर सकती है। इसके अलावा यह परमाणु मिसाइल को 400 किलोमीटर पहले ही नष्ट कर सकता है। इसके तीन प्रमुख अंग हैं जिनमें मिसाइल लॉन्चर, रडार और कमांड सेंटर शामिल है।
- यह प्रणाली एक ही समय में 100 हवाई लक्ष्यों को ट्रैक करने के साथ छह लक्ष्यों को एक साथ भेद सकती है। यह रूस की लम्बी दूरी की मिसाइल रक्षा प्रणाली की चौथी पीढ़ी है।
- S-400 वायु रक्षा प्रणाली एक बहुक्रियात्मक रडार, लक्ष्य को स्वयं से पहचानने एवं उसे लक्ष्यीकृत करने की प्रणाली के साथ-साथ विमान-रोधी मिसाइल प्रणाली, लॉन्चर तथा कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से सुसज्जित है।

भारत को इसकी आवश्यकता क्यों है?

- भारत के साथ रूस की डील तय हो चुकी है और अब आपूर्ति होना बाकी है। इस मिसाइल को रूस की सेना में 2007 में शामिल किया गया था। रूस ने सबसे पहले तुर्की को इसकी आपूर्ति की थी। रूस ने इसे सीरिया में 2015 में तैनात किया था । भारत के दृष्टिकोण से चीन भी इस प्रणाली को खरीद रहा है। वर्ष 2015 में चीन ने इस प्रणाली की छह बटालियन खरीदने के लिये समझौते किया, जिसकी डिलीवरी जनवरी 2018 में शुरू हुई।
- चीन के S-400 प्रणाली के अधिग्रहण को क्षेत्र में 'गेम चेंजर' के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि, भारत के खिलाफ इसकी प्रभावशीलता सीमित है। विशेषज्ञों के अनुसार, भले ही भारत-चीन सीमा पर इसे तैनात किया गया हो किन्तु हिमालय के पहाड़ी क्षेत्रों की ओर स्थानांतरित किये जाने की स्थिति में भी दिल्ली मुश्किल से ही इसकी परिधि में आएगी।
- जानकारों का मानना है कि दोहरे-मोर्चे अर्थात चीन, पाकिस्तान के साथ युद्ध की स्थिति में F-35 जैसे लड़ाकू विमान का सामना करने के लिये भारत का यह अधिग्रहण महत्वपूर्ण है।
- भारत को पड़ोसी देशों के खतरे से निपटने के लिए S-400 की खासी जरूरत है। पाकिस्तान के पास अपग्रेडेड एफ-16 से लैस 20 फाइटर स्क्वैड्रन्स हैं। इसके अलावा उसके पास चीन से मिले J-17 भी बड़ी संख्या में हैं। पड़ोसी देश और प्रतिद्वंद्वी चीन के पास 1,700 फाइटर है, जिनमें 800 4-जेनरेशन फाइटर भी शामिल हैं। ऐसे में S-400 भारतीय वायुसेना के लिए एक बूस्टर शॉट जैसा साबित होगा।

- भारतीय वायुसेना के पास लड़ाकू विमानों की कमी के चलते दुश्मनों से निपटने की उसकी क्षमता प्रभावित हुई है। इसलिए जरूरत है कि हम अपने प्रतिद्वंद्वियों से निपटने के लिए पर्याप्त ताकत जुटाकर रखें।

रक्षा सौदे पर काटसा की पेंच एवं भारत

- भारत ने अमेरिका से दो टूक कहा कि रूस के साथ एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम एस-400 को लेकर हुए करार पर वह किसी दबाव के आगे नहीं झुकेगा। एस-400 को लेकर 'काटसा' (काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट) के तहत प्रतिबंधों पर जुलाई 2018 में अमेरिका ने कहा था कि वह भारत, इंडोनेशिया और वियतनाम को सी.ए.ए.टी.एस.ए. प्रतिबंधों में छूट देने के लिये तैयार है।
- काटसा (2 अगस्त, 2017 को अधिनियमित और जनवरी 2018 से लागू)के तहत ईरान, उत्तर कोरिया और रूस के साथ कारोबार करने वाले किसी भी देश को प्रतिबंधों का सामना करना पड़ेगा। इस कानून का उद्देश्य दंडनीय उपायों के माध्यम से ईरान, रूस और उत्तरी कोरिया की आक्रामकता का सामना करना है।
- काटसा अधिनियम की धारा 235 में 12 प्रतिबंधों का वर्णन किया गया है, जिसमें कुछ निर्यात लाइसेंस पर प्रतिबंध तथा प्रतिबंधित व्यक्तियों द्वारा रक्षा और खुफिया क्षेत्रों में अमेरिकी निवेश पर प्रतिबंध शामिल हैं।

भारत की चिंताएं

- अमेरिकी विदेश विभाग ने काटसा CAATSA कानून के तहत 39 ऐसी रूसी संस्थाओं को अधिसूचित किया है, जिनके साथ समझौता करने वाले पक्षों या देशों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। विदित हो कि S-400 की निर्माता कम्पनी (ALMAZ-ANTEY AIR AND SPACE DEFENSE CORPORATION JSC) उन 39 संस्थाओं की सूची में शामिल है। ऐसे में यदि CAATSA को कड़ाई से लागू किया जाता है, तो रूस से भारत की रक्षा खरीद प्रभावित हो सकती है।
- S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के अलावा, 'प्रोजेक्ट 1135.6' के तहत युद्धपोत और KA226T हेलीकॉप्टर भी CAATSA कानून से प्रभावित होंगे। साथ ही, यह इंडो रूसी एविएशन लिमिटेड, मल्टी-रोल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट लिमिटेड और ब्रह्मोस एयरोस्पेस जैसे संयुक्त उपक्रमों को प्रभावित करेगा। यह भारत के स्पेयर पार्ट्स, घटकों, कच्चे माल और अन्य सहायता की खरीद को भी प्रभावित करेगा।

आगे की राह

- अमेरिका भारत को अपने रक्षा उद्योग के लिए एक प्रमुख बाजार के रूप में देखता है। पिछले एक दशक में, शून्य से 15 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक के हथियारों के सौदे में वृद्धि हुई है। पिछले कुछ वर्षों में भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक संबंधों में भी काफी तेजी आई है। ऐसे में अमेरिकी प्रशासन से कम ही उम्मीद है कि CAATSA कानून दोनों देशों के बीच गहरे होते रिश्ते के लिये बाधक होगा। जानकारों की मानें तो ट्रम्प प्रशासन ने चीन की बढ़ती गतिविधियों के चलते अपनी हिंद-प्रशांत नीति में भारत को ज्यादा महत्व देना शुरू किया था। पेंटागन की रिपोर्ट में कहा गया था कि हिंद महासागर और उसके आसपास के इलाकों की सुरक्षा के लिए अमेरिका भारत के साथ सहयोग बढ़ाएगा। अमेरिका इस क्षेत्र में हर तरह से भारत के नेतृत्व का समर्थन करेगा।
- CAATSA कानून से भारत को छूट देने से चीन को नियंत्रित किया जा सकता है, साथ ही हिंद-प्रशांत और क्वाड जैसे रणनीतिक मंच पर भारत का सहयोग प्राप्त करना अमेरिका के लिए आसान होगा।
- इस प्रकार भारत को उम्मीद है कि अमेरिका, भारत की सुरक्षा अनिवार्यताओं को समझता है।

सामान्य अध्ययन पेपर-2

Topic:

- द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और भारत से संबंधित और/ अथवा भारत के हितों को प्रभावित करने वाले समझौते।

Topic:

- भारत के हितों, भारतीय डायसपोरा पर विकसित तथा विकासशील देशों की नीतियों तथा राजनीति का प्रभाव।

प्र. क्या CAATSA कानून के पेंच से हिंद-प्रशांत और क्वाड जैसे रणनीतिक मंच पर भारत का सहयोग प्राप्त करना अमेरिका के लिए आसान होगा? चर्चा कीजिये।

05 बड़े उद्यमियों के हाथों में बैंकिंग सेक्टर : एक अवलोकन

चर्चा का कारण

- हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गठित इंटरनल वर्किंग ग्रुप (Internal Working Group-IWG) ने बैंकिंग नियमन कानून, 1949 में जरूरी संशोधन के बाद बड़ी कंपनियों को बैंकों का प्रमोटर बनने की अनुमति देने का प्रस्ताव किया है। यही नहीं, वर्किंग ग्रुप ने बड़ी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFC) को बैंकों में तब्दील करने का भी प्रस्ताव दिया है। हालांकि रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन और पूर्व डिप्टी गवर्नर विरल आचार्य ने कॉरपोरेट घरानों को बैंक स्थापित करने की मंजूरी देने की सिफारिश की आलोचना की है।

इंटरनल वर्किंग ग्रुप की प्रमुख सिफारिशें

- ऐसे गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFC) को बैंकिंग लाइसेंस देने की वकालत की गई है, जिनकी संपत्ति 50,000 करोड़ रुपये से ज्यादा है और जिनका कम से कम 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है।
- समिति ने कहा है कि भुगतान बैंक को लघु वित्त बैंक में बदलने पर लगने वाला समय भी कम किया जाना चाहिए, अर्थात पेमेंट बैंक को छोटे वित्तीय बैंक में आसानी से बदलने के लिए उनके ट्रैक रिकॉर्ड देखने की शर्त को पांच साल से घटाकर तीन साल कर दिया जाए।
- किसी बैंक की स्थापना के 15 साल हो जाने के बाद उसमें प्रमोटर की हिस्सेदारी बढ़ाकर 26 फीसदी तक करने की इजाजत दी जाए। अभी यह सीमा 15 फीसदी तक है।
- नए बैंक खोलने के लिए शुरुआती पूंजी या नेटवर्थ की जरूरत को 500 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1,000 करोड़ रुपये किया जाए। छोटे वित्तीय बैंकों के लिए नेटवर्थ की जरूरत को 200 करोड़ बढ़ाकर 300 करोड़ रुपये किया जाए।
- इसी तरह जो सहकारी बैंक छोटे वित्तीय बैंक बनना चाहते हैं, उनके लिए नेटवर्थ की जरूरत सिर्फ 150 करोड़ रुपये हो, लेकिन इसे अगले पांच साल में बढ़ाकर 300 करोड़ रुपये किया जाए।

औद्योगिक समूहों को बैंकिंग लाइसेंस देने से जोखिम

- 'कनेक्टेड लैंडिंग' यानी ऐसी व्यवस्था जिसमें बैंक का मालिक अपनी ही कंपनी को आसान शर्तों पे लोन दे देता है। S-P ग्लोबल रेटिंग्स के अनुसार इससे हितों का टकराव, आर्थिक ताकत के केंद्रीकरण और वित्तीय अस्थिरता जैसे खतरे हो सकते हैं। इसके अलावा इंटर ग्रुप लेंडिंग, फंड का डायवर्जन, कॉरपोरेट डिफाल्ट बढ़ने जैसे खतरे हैं। हाल में यस बैंक, ICICI बैंक, डीएचएफल, पीएमसी जैसे बैंकों के मामले में यह देखा है कि कॉरपोरेट गठजोड़ से किस तरह से घोटालों को अंजाम दिया गया और फंड का डायवर्जन किया गया।
- इससे पूंजी कुछ पारिवारिक घरानों तक सिमट जाने का डर रहता है। बैंकों में जनता का पैसा जमा होता है और कॉरपोरेट घराने कई तरह के बिजनेस में लगे होते हैं जिनमें उन्हें पूंजी की जरूरत पड़ती है। तो इस बात की आशंका है कि ऐसे बैंकों का फंड किसी और बिजनेस में डायवर्ट हो जाए, कॉरपोरेट से जुड़ी दूसरी कंपनियों को लोन दे दिया जाए। यह लोन डिफाल्ट होगा तो बैंक पर खतरा आएगा और जनता का पैसा जोखिम में पड़ जाएगा।
- इससे गंभीर वित्तीय संकट भी खड़ा हो सकता है। साल 2008 में आयी अंतरराष्ट्रीय मंदी की प्रमुख वजह निजी अमेरिकी बैंकों का फेल होना ही था।
- साल 1969 में बैंकों के राष्ट्रीयकरण से पहले ऐसे कई उदाहरण और घपले सामने आये जिसमें बैंकों से जुड़े बड़े कॉरपोरेट घरानों ने खुद को ही लोन दे दिया और एनपीए में उनका बड़ा हिस्सा था। मार्च 2018 तक के आंकड़ों को देखें तो भारतीय बैंकों का फंसा कर्ज करीब 9.62 लाख करोड़ रुपये का था, जिसमें से करीब 73 फीसदी हिस्सा (7.04 लाख करोड़ रुपये) कॉरपोरेट-इंडस्ट्री जगत का ही है। इसलिए अब ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है।

- कॉरपोरेट घरानों द्वारा चलाए जा रहे बैंक आगे चलकर नैतिक जोखिम और ऋण आवंटन की पूर्ण विकृति को आमंत्रित कर सकते हैं। यह किसानों और लघु तथा मध्यम उद्योगों को ऋण प्राप्त करने से दूर करेगा। वित्तीय-औद्योगिक समूह से संबंधित बड़ी कंपनियां पसंदीदा शर्तों पर ऋण प्राप्त करेंगी।
- राजनीतिक संपर्क वाले बिजनेस घराने सबसे पहले बैंकिंग लाइसेंस हासिल कर लेंगे और अपना एकाधिकार स्थापित कर लेंगे।

औद्योगिक समूहों को बैंकिंग लाइसेंस देने के लाभ

- भारतीय अर्थव्यवस्था की जरुरतें और आकांक्षाएं इस तरह की है जिसको देखते हुए बैंकिंग क्षेत्र में बड़ी पूंजी के स्रोतों को प्रवेश देने पर विचार करने की जरूरत है। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था प्राप्त करने के लिए काफी पूंजी की जरूरत होगी और नए निजी बैंक से इसमें मदद मिल सकती है। निजी क्षेत्र का पेशेवर प्रबंधन, विशेषज्ञता बैंकिंग सेक्टर को मजबूत कर सकता है।
- निजी बैंक ज्यादा सक्षम और मुनाफे में हैं और ग्राहकों को पेशेवर तरीके से सेवाएं दे रहे हैं।
- रिजर्व बैंक के वर्किंग ग्रुप का यह मानना है कि कॉरपोरेट को बैंकिंग में आने की इजाजत देने से बैंकिंग सेक्टर के लिए पूंजी का अच्छा स्रोत मिल सकता है।
- इसके अलावा कॉरपोरेट के आने से बैंकों में मैनेजमेंट विशेषज्ञता, अनुभव, सही दिशा मिल सकती है। समूह ने इस बात पर गौर किया है कि दुनिया के बहुत से देशों में कॉरपोरेट को बैंकिंग सेक्टर में काम करने की इजाजत दी गयी है।

रिजर्व बैंक का मत

- रिजर्व बैंक का बड़ी कंपनियों/औद्योगिक घरानों द्वारा बैंकों के स्वामित्व को लेकर रुख सतर्क रहा है। इसका कारण इससे जुड़ा जोखिम, संचालन को लेकर चिंता और हितों का टकराव है।
- यह स्थिति उस समय उत्पन्न हो सकती है जबकि बैंकों पर बड़ी कंपनियां या औद्योगिक घरानों का स्वामित्व होगा। आरबीआई ने पहली बार 2013 में निजी क्षेत्र में नये बैंक के लाइसेंस के लिये अपने दिशानिर्देश में 'नॉन-ऑपरेटिव फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी' (एनओएफएचसी) के तहत बैंक के प्रवर्तन के लिये कई संरचनात्मक जरूरतों को निर्धारित किया था।

देश में एनबीएफसी

- देश में 9601 एनबीएफसी हैं। 31 मार्च, 2009 से लेकर 31 मार्च, 2019 के बीच NBFCs की सालाना विकास दर 18.6% रही है। जबकि इस दौरान कामर्शियल बैंक की विकास दर 10.7% रही। एनबीएफसी की कुल बैलेंस शीट साइज कामर्शियल बैंक की कुल बैलेंस शीट साइज की 18.6% है। मार्च 2009 में यह महज 9.3% थी। RBI के IWG ने कहा, 31 मार्च, 2020 तक NBFC का असेट साइज (asset size) 51 लाख करोड़ रुपए से अधिक रही है।

निष्कर्ष

- एक स्वच्छ विश्वसनीय और ठोस वित्तीय क्षेत्र जैसे बैंक अर्थव्यवस्था के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था हासिल करने के लिए वित्तीय ढांचा विकसित होते रहने चाहिए और अधिक से अधिक सुदृढ़ होना चाहिए। बैंक को मजबूत बनाने और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को पूंजी के माध्यम से अधिक प्रतिस्पर्धी, पारदर्शी और व्यवसायिक बनाने के लिए इनमें शासन संबंधी सुधार किए जाने चाहिए। इसके अतिरिक्त सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ बैंकों को अतिरिक्त पूंजी जुटाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। निष्कर्षत: औद्योगिक समूहों को बैंकों का प्रायोजक बनने या बैंकिंग लाइसेंस देने की अनुमति से पहले लाभ एवं नुकसान की व्यापक समीक्षा कर अध्ययनों पर जोर देने की आवश्यकता है।

सामान्य अध्ययन पेपर-3

Topic:

- भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना, संसाधनों को जुटाने, प्रगति, विकास तथा रोजगार से संबंधित मुद्दे।

प्र. औद्योगिक समूहों को बैंकिंग लाइसेंस देने के लाभ एवं नुकसान के अध्ययनों पर जोर देने की आवश्यकता है। चर्चा कीजिये।

06 कृषि का व्यवसायिकरण : एक नया दृष्टिकोण

चर्चा का कारण

- ग्रामीण कृषि आधारित उद्योगों में बहुत बड़ी संभावनाएं हैं और इसके लिए एक अनुकूल नीतिगत व्यवस्था मौजूद है। ग्रामीण, अर्ध-ग्रामीण और श्रेणी-2 तथा श्रेणी-3 शहरों में हो रहे सकारात्मक बदलावों का मजबूती से पक्ष लेते हुए हाल ही में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने व्यवसाय और उद्योग जगत के वरिष्ठ प्रमुखों को ऐसे क्षेत्रों में अवसरों का लाभ उठाने के लिए आमंत्रित किया है।

परिचय

- केंद्र सरकार कृषि क्षेत्र को उच्च प्राथमिकता देती है। किसानों को अवसर प्रदान करके उनकी आय बढ़ाने के साथ ही ज्यादा से ज्यादा युवाओं को रोजगार प्रदान करने पर भी सरकार का ध्यान है। इसी तारतम्य में कृषि से जुड़े स्टार्ट-अप्स को बढ़ावा दिया जा रहा है।
- भारत सरकार का जोर कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में नवाचार एवं प्रौद्योगिकी का उपयोग सुनिश्चित करने के लिए स्टार्ट-अप्स और कृषि-उद्यमिता को बढ़ावा देने पर है। इसी के तहत राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) के अंतर्गत 'नवाचार और कृषि-उद्यमिता विकास' कार्यक्रम को अपनाया गया है।
- कृषि क्षेत्र उद्योगों के विशाल क्षेत्र के लिए भोजन, चारा और कच्चे माल की सप्लाई करता है। भारत में कृषि क्षेत्र अभी भी लाखों लोगों की आजीविका का प्राथमिक स्रोत है और देश में कुल कार्यबल का 40 फीसद से अधिक अभी भी अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर करता है। इसलिए, न केवल ग्रामीण लोगों के बीच खरीद क्षमता उत्पन्न करने के लिए, बल्कि कीमतों में स्थिरता, मांग में बढ़ोत्तरी और रोजगार सृजन के लिए कृषि क्षेत्र में लगातार वृद्धि अनिवार्य है।
- किन्तु दूसरी ओर देखा जाये तो कृषि को व्यवसाय के रूप में नहीं देखा गया है। आजादी के बाद लगातार सरकारों द्वारा खाद्य सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों के समाधान के लिए प्रयास किए गए हैं। लेकिन जब खाद्य सुरक्षा हासिल कर ली गई और भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में गेहूं और चावल के स्टॉक सड़ने लगे, तो सरकारों द्वारा किसानों को व्यवसाय के रूप में कृषि पर प्राथमिकता नहीं दी गयी।

किसानों की आय दोगुना करने का लक्ष्य

- पिछले कुछ वर्षों के दौरान, कृषि क्षेत्र के विकास और किसानों की आय को दोगुना करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा कई तरह की योजनाओं और पहलों की घोषणा की गई है। इनमें से कुछ प्रमुख योजनाएं मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, राष्ट्रीय कृषि बाजार (NAM) के तहत अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का शुभारंभ, प्रधानमंत्री आवास बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY), समर्पित ऑनलाइन इंटरफेस ई-कृषि संवाद, किसान उत्पाद संगठनों (FPQ), माइक्रो इरिगेशन फंड (MIF), पशुधन, मछुआरों और अन्य लोगों के लिए योजनाओं के अनुकूल कराधान हैं।

भारत कई कृषि और संबंधित उत्पादों का प्रमुख उत्पादक है

- भारत को विश्व स्तर पर कई कृषि और संबंधित उत्पादों का प्रमुख उत्पादक माना जाता है। विश्व स्तर पर, भारत को विविध कृषि जलवायु क्षेत्रों की उपलब्धता के साथ दूध, केला, आम, अमरूद, पपीता, अदरक, भिंडी, गेहूं, चावल, फल, सब्जियां, चाय, गन्ना, काजू, अनाज, नारियल, सलाद पत्ता (लेट्टूस), चीकरी, इलायची और काली मिर्च के प्रमुख उत्पादक के रूप में जाना जाता है।
- भारत दुनिया की 2.4 फीसद भूमि और 4 फीसद जल संसाधन के साथ दुनिया की लगभग 18 फीसद आबादी का भरण-पोषण कर रहा है। इसलिए उत्पादकता, फसल कटाई के पूर्व और पश्चात प्रबंधन, प्रसंस्करण और मूल्य-संवर्धन, प्रौद्योगिकी का उपयोग और बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए निरंतर प्रयास भारतीय कृषि के लिए आवश्यक हैं।

कृषि क्षेत्र में विकास और निर्यात को बढ़ावा देने के उपाय

- कृषि क्षेत्र की वृद्धि के लिए कृषि अनुसंधान, विस्तार और शिक्षा की आवश्यकता है । कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में नवाचार एवं प्रौद्योगिकी का उपयोग सुनिश्चित करने के साथ-साथ कृषि सहायक संसाधनों और बुनियादी सुविधाओं के लिए एक स्थान पर जानकारियाँ उपलब्ध कराने हेतु माहौल को बेहतर बनाने की आवश्यकता है।

- भारत का विकास गांवों और छोटे शहरों द्वारा संचालित होता है। ऐसे में सरकार को उद्यमियों को गांवों और छोटे शहरों में निवेश करने का माहौल प्रदान करना चाहिए। उद्यमियों का निवेश ग्रामीण और कृषि क्षेत्रों में नए दरवाजे खोलेगा। इसके अतिरिक्त कच्चे माल के सप्लायरों और प्रसंस्करण यूनिटों के बीच मजबूत संबंध बनाने के लिए बाजारों का गांवों से संपर्क बेहतर करने की प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
- बेहतर और अनुकूल कामकाजी माहौल बनाने के लिए, जनशक्ति के प्रशिक्षण और कौशल विकास, निरंतर प्रौद्योगिकी अपग्रेडेशन, विविधीकरण और उत्पादों की मार्केटिंग, खाद्य सुरक्षा और आवश्यकताओं के बारे में जानकारियों में बढ़ोतरी को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त अनुसंधान और विकास, विशेष रूप से पैकेजिंग, उत्पाद विकास, खाद्य प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में, को मजबूत बनाने की आवश्यकता है।
- फसलों से जुड़े सभी प्रकार के शासकीय कार्यक्रमों का लाभ किसानों तक पहुंचाने के लिए विशेष अभियान के तहत विभिन्न प्रकार के उपकरण व अन्य आदान, जो किसानों को दिलाया जाना है, उसे अभियान के रूप में उपलब्ध कराया जाए। जैविक खेती के प्रति आकर्षण को और बढ़ाना होगा। इतना ही नहीं प्रसंस्करण, भंडारण और फसलोत्तर प्रबंधन के प्रति जागरूकता अभियान चलाया जाना भी किसानों के लिए हितकर होगा।
- खेत में कल्टीवेटर, रोटा वेटर या डिस्क हेरो आदि की सहायता से फसल अवशेषों को भूमि में मिलाने से आने वाली फसलों में जीवांश के रूप में खाद की बचत की जा सकती है। इसके लिए किसान हलधर योजना का लाभ लेकर गहरी जुताई भी कर सकते हैं। किसान सामान्य हार्वेस्टर्स से गेहूं कटवाने के स्थान पर स्ट्रा रीपर एवं हार्वेस्टर्स का प्रयोग करें तो पशुओं के लिए भूसा और खेत के लिए बहुमूल्य पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ने के साथ मिट्टी की संरचना को बिगड़ने से भी बचाया जा सकता है।

आगे की राह

- मध्यम और लंबी अवधि में, कृषि क्षेत्र में कृषि उत्पादकता और किसानों की आय को बढ़ावा देने के लिए व्यापक सुधार की आवश्यकता है। किसानों की पूंजी की लागत को कम करने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए ताकि वे कम लागत की उधारी पर कृषि गतिविधियों को करने में सक्षम हो सकें।
- गांवों की आसान पहुंच के भीतर, विशेष रूप से अत्यंत छोटे किसानों के लिए पर्याप्त और कुशल वेयरहाउसिंग की सहायता प्रदान करने की आवश्यकता है। इससे वे अपनी उपज को न्यूनतम कीमतों पर स्टोर कर सकते हैं, और ऋण के लिए भंडारण की रसीद का उपयोग कर सकते हैं, या बाद में कीमत बढ़ने पर अनाज को बाजार में बेच सकते हैं।
- इसके अलावा, आगे जिन क्षेत्रों पर ध्यान दिया जाना चाहिए उनमें किसानों को मशीनीकृत खेती को अपनाने के लिए शिक्षित करना, बर्बादी को 30 से 35 फीसद के मौजूदा स्तर से 10 फीसद तक कम करना, कृषि क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश बढ़ाना, तकनीकी सुधार के साथ कृषि को और अधिक आधुनिक बनाना अहम है।
- कृषि विस्तार विकास कार्यक्रमों के साथ ही शोध और अनुसंधान की दिशा में भी प्रयासों की जरूरत है ताकि कीट व्याधि और पाले आदि की समस्याओं का सामना करने में सक्षम प्रजातियों का विकास हो सके। किसानों को समय से और सही खाद, बीज, औषधि और उपकरण प्राप्त हो, इसके लिए अग्रिम रूप से समुचित प्रबंध किए जाने चाहिए।

सामान्य अध्ययन पेपर-2

Topic:

- सरकारी नीतियों और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप और उनके अभिकल्पन तथा कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न मुद्दे।

सामान्य अध्ययन पेपर-3

Topic:

- प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कृषि सहायता तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य से संबंधित विषय, जन वितरण प्रणाली-उद्देश्य, कार्य, सीमाएं, सुधार; बफर स्टॉक तथा खाद्य सुरक्षा संबंधी मुद्दे; प्रौद्योगिकी मिशन; पशु पालन संबंधी अर्थशास्त्र।

प्र. खेती को लाभ का व्यवसाय बनाने के लिए अन्य सकारात्मक कदमों के साथ-साथ शोध और अनुसंधान की दिशा में प्रयास करने की आवश्यकता है। चर्चा कीजिये।

07 विकास और स्मृद्धि के लिए पूर्वोत्तर राज्यों से समुचित जुड़ाव की आवश्यकता

चर्चा का कारण

- पूर्वोत्तर (north east) राज्यों को ऐतिहासिक रूप से शेष भारत और पड़ोसी देशों के साथ खराब परिवहन, व संचार का सामना करना पड़ा है। इससे न केवल रोजमर्रा की जिंदगी और आजीविका, बल्कि क्षेत्रीय विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा भी बाधित हुई है। इस मामले में देखा जाये तो चीन अपने स्वयं के सीमावर्ती क्षेत्रों के साथ-साथ एशिया और यूरोप के राजमार्गों के माध्यम से अपने पड़ोसी क्षेत्रों में अपनी पकड़ मजबूत करता रहा है, किन्तु भारत उत्तर पूर्वी राज्यों सहित सीमावर्ती से सटे गाँव में सड़क अवसंरचना व संचार की दृष्टि से अब भी पीछे है।

परिचय

- भारत का पूर्वोत्तर क्षेत्र एशिया-दक्षिण एशिया तथा दक्षिण पूर्व एशिया के उप क्षेत्रों के बीच सेतु के रूप में कार्य करता है। दोनों ही क्षेत्रों में व्यापक सकारात्मक बदलाव हो रहे हैं जिसे आर्थिक प्रगति एवं विकास से और भी गति मिल रही है।
- पूर्वोत्तर क्षेत्र के मानचित्र पर नजर डालने पर यह पता चलता है कि लगभग पूरा ही क्षेत्र विदेशी राज्यों से घिरा हुआ है तथा इस क्षेत्र की सातों बहनें अवस्थिति के आधार पर सहवर्ती असुविधा के कारण आंतरिक आधार पर आबद्ध हैं, जबकि यह तथ्य भी सही है कि इनमें से प्रत्येक राज्य की सीमा कम से कम एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ लगती है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र का सामरिक महत्व

- पूर्वोत्तर क्षेत्र पांच एशियाई राज्यों-चीन, नेपाल, भूटान, म्यामांर और बंगलादेश से घिरा हुआ है। अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड की 1643 किमी. लम्बी सीमा म्यामांर के साथ लगती है; असम,मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम की 1880 किमी. लम्बी सीमा बंगलादेश के साथ लगती है; अरुणाचल प्रदेश, असम और सिक्किम की 468 किमी. सीमा भूटान से लगती है; अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम की 1325 किमी. सीमा चीन लोक गणराज्य के तिब्बत स्वायत्तशासी क्षेत्र के साथ लगती है।

- 1947 के विभाजन के परिणामस्वरूप सम्पर्क सुविधा और बाजार पहुंच में हुई क्षति के कारण इस क्षेत्र में उत्पन्न कठिनाइयों की जानकारी सभी को है। पारम्परिक परिवहन मार्ग, रेल, सड़क तथा नदी, चटगांव एवं कलकत्ता बंदरगाहों के साथ सम्पर्क अचानक अनुपलब्ध हो गया और वैकल्पिक मार्गों पर बहुत अधिक व्यय की संभावना थी। उदाहरण के लिए अगरतला और कलकत्ता बंदरगाह के बीच की दूरी 1700 किमी. है जबकि पूर्व पाकिस्तान और आज के बंगलादेश से जाने पर पहले यह दूरी मात्र 375 किमी. थी। इसके फलस्वरूप बाजार और संभारतंत्रों में भारी व्यतिक्रमण आया जिसका दंश भारत का पूर्वोत्तर क्षेत्र अभी भी झेल रहा है।

पूर्वोत्तर राज्यों में विकास के लिए पहल

- डिजिटल नॉर्थ ईस्ट विजन: भारत सरकार ने वर्ष 2018 में डिजिटल नॉर्थ ईस्ट विजन 2022 जारी किया था। यह दृष्टि पत्र डिजिटल प्रौद्योगिकी का फायदा उठाते हुए पूर्वोत्तर के लोगों के जीवन स्तर बदलने और जीवन यापन की सुगमता सुनिश्चित करने पर जोर देता है। इस दृष्टि पत्र के तहत आठ प्रमुख डिजिटल क्षेत्रों -डिजिटल बुनियादी ढांचा, डिजिटल सेवाएं, डिजिटल सशक्तिकरण, इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण को बढ़ावा, बीपीओ सहित आईटी एवं आईटीईएस को प्रोत्साहन, डिजिटल भुगतान, नवाचार एवं स्टार्टअप और साइबर सुरक्षा की पहचान की गई है। डिजिटल पूर्वोत्तर दृष्टि पत्र 2022 के एक हिस्से के तहत गुवाहाटी में पूर्वोत्तर के लिए एक क्लाउड हब भी स्थापित किया जाएगा।
- सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में विविध बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की एक व्यापक शृंखला को रफ्तार दी है। सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में रेल, सड़क, वायु और अंतर्देशीय जलमार्ग कनेक्टिविटी में सुधार करने पर जोर दिया है और तमाम बिजली परियोजनाओं के साथ यह क्षेत्र अतिरिक्त बिजली उत्पादन करने के लिए तैयार है।
- सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारतमाला परियोजना के पहले चरण के

तहत पूर्वोत्तर के लिए विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम (एसएआरडीपी-एनई) को लागू कर रहा है। इस परियोजना की अवधि पांच साल (2017-18 से 2021-22) तक है और इसके तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र में कुल 3,528 किमी. सड़कों में सुधार किया जाएगा।

- पूर्वोत्तर राज्यों के लिये 20 प्रमुख रेलवे परियोजनाओं के माध्यम से एक रेलवे लिंक प्रदान करने की योजना पर कार्य किया जा रहा है, जिसमें 13 नई लाइनें, 2 गेज रूपांतरण और लगभग 2,624 किलोमीटर की लंबाई के साथ पाँच दोहरीकरण शामिल हैं। परियोजना में नौ किलोमीटर के साथ 23 सुरंगों का निर्माण भी होगा, साथ ही 36 प्रमुख पुल और 147 छोटे पुल भी होंगे।
- पूर्वोत्तर विशेष बुनियादी ढांचा योजना (एनईएसआईडीएस) के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय इस क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जल आपूर्ति, बिजली, कनेक्टिविटी से संबंधित बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है। यह पूर्वोत्तर क्षेत्र की राज्य सरकारों और केन्द्र की मौजूदा योजनाओं के अतिरिक्त है। पूर्वोत्तर परिषद (एनईसी) की निगरानी में थीम आधारित क्षेत्रीय पर्यटन सर्किट को बढ़ावा देने के लिए काम चल रहा है।
- सरकार ने पूर्वोत्तर भारत के आठ राज्यों में दूरसंचार कनेक्टिविटी में सुधार के लिये 15,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है। सरकार द्वारा अरुणाचल प्रदेश में 2817 से अधिक मोबाइल टावर स्थापित करने की योजना है। इसके अतिरिक्त डाकघरों का नेटवर्क, टेलीफोन एक्सचेंज और टेलीफोन कनेक्शन संचार के लिये प्रमुख बुनियादी ढाँचे हैं। टेलीफोन आधारित संचार में काफी तेज गति से प्रसार हो रहा है।
- इस प्रकार चीन को ध्यान में रखते हुए भारत कई सड़क और सेतु परियोजनाओं पर काम कर रहा है ताकि बांग्लादेश, नेपाल और म्यांमार के साथ संपर्क बेहतर बनाया जा सके। इनमें मिजोरम में आइजल से म्यांमार में कलादन और मणिपुर में इंफाल से म्यांमार में तामू को जोड़ने वाली सड़कें शामिल हैं।
- सरकार पूर्वोत्तर राज्यों में पूर्वोत्तर औद्योगिक विकास योजना के माध्यम से रोजगार को प्रोत्साहित करने के लिए मुख्य रूप से एमएसएमई क्षेत्र को प्रोत्साहन दे रही है।

चुनौतियाँ

- विभिन्न सरकारों के प्रयासों के बावजूद भारत का पूर्वोत्तर क्षेत्र देश के सर्वाधिक पिछड़े क्षेत्रों में से एक है। यहां की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, निजी निवेश की कमी है, पूंजीगत निर्माण का स्तर निम्न है, अवसंरचनागत सुविधाएं पर्याप्त नहीं हैं, यह क्षेत्र भौगोलिक दृष्टि से अलग-थलग है और उसके खनिज संसाधनों, जल ऊर्जा क्षमता और जैव विविधता का पर्याप्त रूप से प्रयोग नहीं किया गया है।
- भौगोलिक अलगाव और कुछ अन्य अंतर के कारण इस इलाके को कई मोर्चों पर पिछड़ेपन और विकास की अनदेखी का सामना करना पड़ा है। फसलों का कम उत्पादन, बैंकों से कर्ज की दिक्कत, बड़े उद्योगों की कमी और अवसंरचना सुविधाओं का अभाव आदि ने इस क्षेत्र के समग्र विकास को बाधित किया है।
- शिक्षा के लिए बेहतर सुविधाओं की कमी और कौशल विकास की दिक्कत के कारण युवाओं को पढ़ाई के लिए अन्य इलाकों में जाने को मजबूर होना पड़ा है।
- इस क्षेत्र में लंबे समय से महिलाओं को कम अवसर प्राप्त होता रहा है और परिवार और वित्तीय मामलों में उनका कोई दखल नहीं होता। स्वयं सहायता समूह बनाने जैसी पहल से इस क्षेत्र में महिलाओं के सशक्तिकरण में मदद मिल सकती है किन्तु पितृवादी सोच के कारण यहाँ लैंगिक सशक्तिकरण की दिशा में उल्लेखनीय सुधार नहीं हुए हैं।

आगे की राह

- देश के अन्य भागों एवं राज्यों में आजीविका और नए उद्यमों के सभी मार्ग धीरे-धीरे समाप्त हो रहे हैं जबकि पूर्वोत्तर क्षेत्र में अपार संभावनाएं अभी भी मौजूद हैं। ऐसे में भारत सरकार की प्रमुख पहल 'मेक इन इंडिया' की तर्ज पर 'मेक इन पूर्वोत्तर' के लिए सरकार को युवा उद्यमियों को पूर्वोत्तर आने के लिए प्रेरित करना चाहिए।
- भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में अपार प्राकृतिक संसाधन हैं। यहां देश के 34% जल संसाधन हैं और 40% जलऊर्जा की क्षमता है। यह क्षेत्र पूर्व के मुख्य देशों तथा बांग्लादेश एवं म्यांमार जैसे पड़ोसी देशों के निकट होने के कारण कूटनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, चूंकि यहां से पूर्वी भारत के परंपरागत घरेलू बाजार तक पहुंच बनती है। दक्षिण एशियाई बाजार में सुविधाजनक तरीके से प्रवेश करने के लिए यह क्षेत्र महत्वपूर्ण है। अपार संसाधन, ऊपजाऊ कृषि भूमि और अकूत मानव पूंजी-इन सबके साथ यह क्षेत्र देश के सर्वाधिक संपन्न क्षेत्रों में से एक हो सकता है।

सामान्य अध्ययन पेपर-2

Topic:

- सरकारी नीतियों और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप और उनके अभिकल्पन तथा कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न मुद्दे।

सामान्य अध्ययन पेपर-3

Topic:

- बुनियादी ढांचा: ऊर्जा, बंदरगाह, सड़क, विमानपत्तन, रेलवे आदि।

प्र. उत्तर-पूर्वी राज्यों में बुनियादी ढांचागत विकास पर सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों की चर्चा कीजिये।

7 महत्वपूर्ण ब्रेन बूस्टर्स

01 हवाना सिंड्रोम

1. चर्चा का कारण

- वर्ष 2016 में क्यूबा, चीन और अन्य देशों में अमेरिकी राजनयिक एक रहस्यमय न्यूरोलॉजिकल बीमारी जिसे हवाना सिंड्रोम कहा जा रहा है, से प्रभावित हुए थे। अमेरिका की नेशनल एकेडेमीस ऑफ साइंसेस (National Academies of Sciences-NAS) की वर्तमान रिपोर्ट के अनुसार यह बीमारी संभवत: निर्दिष्ट' माइक्रोवेव विकिरण (directed microwave radiation) के कारण होती है।

2. हवाना सिंड्रोम

- वर्ष 2016 में क्यूबा में अमेरिकी दूतावास के अधिकारियों ने शिकायत की थी कि उन्हें उल्टी, नाक से खून और बेचैनी हो रही है। इस मामले के बाद इसे हवाना सिंड्रोम कहा जाने लगा था।
- कहा जाता है कि अमेरिकी अधिकारियों के खिलाफ छिपकर सोनिक वेपन का इस्तेमाल किया गया था। अमेरिकी अधिकारियों ने इसी तरह की घटनाओं की शिकायत चीन और रूस में भी की है। उन्होंने कहा कि दूतावास की इमारत के कुछ कमरों में उन्हें इस तरह की दिक्कत का सामना करना पड़ा।
- इस बीमारी के कुछ लक्षणों में मतली (मिचली), थकान, मानसिक परेशानी और चक्कर आना शामिल हैं।इस बीमारी से संक्रमित होने पर, रोगी को पीड़ादायक सनसनाहट और भिनभिनाहट की आवाज महसूस होती है।

3. माइक्रोवेव हथियार

- ये एक प्रकार के प्रत्यक्ष ऊर्जा हथियार (direct energy weapons) हैं। इस हथियार के द्वारा एक लक्ष्य पर ध्वनि, लेजर या माइक्रोवेव ऊर्जा केंद्रित की जाती है। जो लोग उच्च तीव्रता वाले माइक्रोवेव पल्सेस के संपर्क में आते हैं, वे सिर में एक क्लिक या भनभनाने की आवाज महसूस करते हैं। इस हथियार के तीव्र और दीर्घकालिक दोनों प्रभाव हो सकते हैं। हालाँकि इसके कारण शारीरिक क्षति का कोई संकेत नहीं दिखता है।
- माइक्रोवेव हथियार की वेवलेंथ एक मि.मी. से लेकर एक मीटर तक होती है। इनकी फ्रीक्वेंसी 300 मेगाहट्‌र्ज (100 सेंटीमीटर) और 300 गिगाहट्‌र्ज (0.1 सेंटीमीटर) के बीच होती है। इन्हें हाई-एनर्जी रेडियो फ्रीक्वेंसी भी कहा जाता है।
- युद्ध स्तर पर माइक्रोवेव हथियारों का इस्तेमाल कम ही देखा गया है। इसका उपयोग चेतावनी देने के लिए किया जाता है। यदि दुश्मनों पर माइक्रोवेव हथियार से हमला किया जाए तो उन्हें आंखों की समस्या, शरीर में हल्के घाव और अंदरूनी चोटें लग सकती हैं। फिलहाल भारत, चीन, रूस, ब्रिटेन इस हथियार को विकसित करने में जुटे हुए हैं।

02 हम्पी के प्रतिष्ठित पत्थर निर्मित रथ

1. चर्चा का कारण

- हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (Archaeological Survey of India – ASI) ने सुरक्षा के लिहाज से हम्पी में विजय विट्ठल मंदिर के सामने प्रतिष्ठित पत्थर निर्मित रथ (chariot) को छूने से रोकने के लिए सुरक्षात्मक बैरिकेड लगा दिये हैं।

2. आवश्यकता क्यों?

- पत्थर का रथ हम्पी में सबसे अधिक देखे जाने वाले स्मारकों में से एक है और इसके अतिरिक्त सुरक्षा की आवश्यकता है। यहाँ पर आने वाला हर पर्यटक संवेदनशील स्मारक की तस्वीरें खींचता है और उसे छूता है। कुछ तो स्मारक के साथ अपनी तस्वीरें लेने के लिए भी चढ़ते हैं। संरक्षित स्मारक कुछ पर्यटकों के इस तरह के आपत्तिजनक व्यवहार से क्षतिग्रस्त होने का जोखिम उठा रहा है। इसलिए इसके चारों ओर अवरोध खड़ा करना पड़ा है।

3. प्रमुख बिन्दु

- हम्पी रथ भारत के तीन प्रसिद्ध पत्थर रथों में से एक है, अन्य दो कोणार्क (ओडिशा) और महाबलीपुरम (तमिलनाडु) में हैं। विजयनगर के शासकों के संरक्षण में यह मंदिर वास्तुकला का कौशल दर्शाता है, जो 14 वीं से 17 वीं शताब्दी तक शासन करते थे।
- 16वीं शताब्दी में इसका निर्माण विजयनगर शासक राजा कृष्णदेवराय के आदेश पर किया गया था।

4. हम्पी

- यह मध्य कर्नाटक में तुंगभद्रा बेसिन में स्थित है। 1336 में इसकी स्थापना हरिहर और बुक्का ने की थी।
- हम्पी,दक्षिणी भारत के एक पुराने शहर विजयनगर में स्थित एक छोटा सा गाँव है। संस्कृत में विजयनगर का अर्थ 'जीत का नगर' होता है। 1336 से 1565 तक, यह शहर विजयनगर साम्राज्य की राजधानी था। 1986 में इस प्राचीन शहर को यूनेस्को विश्व विरासत स्थल घोषित कर दिया गया।
- हम्पी के आसपास मौजूद ग्रेनाइट पहाड़ियों की गिनती दुनिया के सबसे पुराने पत्थरों में की जाती है।
- तुलुव वंश (Tuluva Dynasty) के महान शासक कृष्णदेव राय ने यहाँ पर सबसे अधिक इमारतें बनवाई थीं। तालीकोटा की लड़ाई (1565 इसवीं) के कारण इसका बड़े पैमाने पर विनाश हुआ। तालीकोटा की लड़ाई, विजयनगर के राजा और बीजापुर, बीदर, अहमदनगर, और गोलकोंडा के चार सुल्तानों की सेनाओं के बीच दक्षिण भारत के दक्कन क्षेत्र में हुई थी।

5. पत्थर निर्मित रथ

- हम्पी की सबसे मशहूर जगह पर पत्थर का बना एक बड़ा सा मंदिर है, जो देखने में एक रथ की तरह लगता है। यह मंदिर विष्णु भगवान के वाहन गरुड़ को समर्पित है। वह पक्षियों के राजा माने जाते थे।
- कहा जाता है कि किसी समय में इस मंदिर के ऊपर गरुड़ की मूर्ती हुआ करती थी, जिनका रूप पक्षी जैसा था। यह भी कहा जाता है कि ग्रेनाइट के ये पहिये किसी समय में घूमा करते थे।

6. विट्ठल मंदिर

- विट्ठल मंदिर में लगभग हर जगह भगवान और पौराणिक लोगों से जुड़ी बातें और उनकी मूर्तियां पत्थरों पर उकेरी गई हैं।
- विट्ठल मंदिर की बनावट सबसे खूबसूरत है। यह द्रविड़ वास्तुकला का एक अद्भुत नमूना है, जिसमें बड़े-बड़े पत्थरों पर बारीक नक्काशी की गई है। इसके प्रांगण में दरवाजे, मंदिर, व मीनारें तथा सुनसान पड़े प्रांगण शामिल हैं।
- 56 खम्बों वाला यह रंगमंडप, विट्ठल मंदिर में मौजूद है। विदित हो कि रंगमंडप के अंदर एक मंच होता है, जिस पर बैठकर पूजा-पाठ जैसे धार्मिक काम किए जाते हैं।

7. द्रविड़ शैली

- द्रविड़ शैली के मंदिर कृष्णा नदी से लेकर कन्याकुमारी तक पाए जाते हैं। इस शैली की शुरुआत 8वीं शताब्दी में हुई और सुदूर दक्षिण भारत में लगभग 18वीं शताब्दी तक बनी रही। जो मंदिर इस शैली से निर्मित होते हैं वह बहुमंजिला होते हैं। द्रविड़ शैली को जन्म पल्लवों ने दिया। इसने उँचाइयाँ चोल काल में हासिल की। मूर्तिकला और चित्रकला का संगम इस शैली के साथ चोल काल के दौरान हो गया था।

03 रोहिंग्या शरणार्थियों का सुदूर द्वीप पर पुनर्वासन

1. चर्चा का कारण

- हाल ही में बांग्लादेश ने 1,600 से अधिक रोहिंग्या शरणार्थियों के पहले समूह को एक सुदूर द्वीप पर भेज दिया है। जिस द्वीप पर रोहिंग्या शरणार्थियों को भेजा जा रहा है उसका नाम भाषण चार' (Bhasan Char) है। इस द्वीप को 20 साल पहले समुद्र में खोजा गया था और यहां अकसर बाढ़ आ जाती है।

2. रोहिंग्या समुदाय

- जटिल रोहिंग्या शरणार्थी संकट अगस्त, 2017 में उस समय पैदा हुआ था जब म्यांमार के पश्चिमी हिस्से में कुछ पुलिस चौकियों पर हमले हुए थे। उन हमलों का आरोप, कथित रूप से रोहिंग्या समुदाय से सम्बद्ध सशस्त्र गुटों पर लगाया गया था। उन हमलों के बाद म्यांमार की सेना और सुरक्षा बलों ने रोहिंग्या अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ व्यवस्थित रूप में हमले किये, जिनमें मुख्य रूप से मुसलमानों के खिलाफ हमले शामिल थे।
- इस कार्रवाई के दौरान बलात्कार एवं हत्याएं की गयीं और हजारों घर जला दिये गये। वैश्विक अधिकारवादी संगठनों एवं संयुक्त राष्ट्र ने इसे जातीय सफाया करार दिया था।
- उन हमलों के बाद बहुत से रोहिंग्या लोग सुरक्षा के लिये बांग्लादेश के लिये भाग निकले और लगभग 7 लाख रोहिंज्या शरणार्थियों ने अपने घर छोड़कर बांग्लादेश में पनाह ली, जिनमें ज्यादातर बच्चे, महिलाएँ और बुजुर्ग थे।

3. वर्तमान स्थिति

- म्यांमार राष्ट्रीयता कानून, 1982 के तहत म्यांमार ने रोहिंग्या आबादी को नागरिकता देने से इनकार कर दिया है।
- फिलहाल रोहिंग्या शरणार्थी बांग्लादेश के तटीय शहर कॉक्स बाजार में शिविरों में रह रहे हैं और यहां करीब दस लाख रोहिंग्या शरणार्थियों के रहने का इंतजाम है। लेकिन शिविर शरणार्थियों से भरे पड़े हैं और अकसर यहां सुविधाओं की कमी रहती है।

4. भाषण चार द्वीप

- भाषण चार द्वीप दक्षिण पूर्वी बांग्लादेश के हतिया द्वीप से 30 किलोमीटर पूर्व में स्थित एक निर्जन द्वीप था। इस द्वीप का निर्माण लगभग दो दशक पूर्व मेघना नदी के मुहाने पर हुआ था।
- यह द्वीप मानसून के दौरान नियमित रूप से डूब जाता था लेकिन अब वहां बाढ़ सुरक्षा तटबंध, मकान, अस्पताल, मस्जिदें आदि हैं। यह द्वीप मुख्य भूमि से 21 मील दूर है। भाषण चार द्वीप लगभग 13,000 एकड़ क्षेत्र में फैला है।

5. चिंताएँ

- दरअसल भाषण चार द्वीप पर हमेशा गंभीर समुद्री तूफान का खतरा मंडराता है और हाई टाईड की स्थिति में द्वीप के पूरी तरह डूब जाने का भी खतरा रहता है। ऐसी तबाही की स्थिति में वहां रोहिंग्या शरणार्थियों को बसाना उन्हें मौत के मुंह में भेजने जैसा होगा।
- गौरतलब है कि संयुक्त राष्ट्र ने पहले ही रोहिंग्या शरणार्थियों को भाषण चार द्वीप में बसाए जाने के प्रस्ताव का विरोध किया था। भाषण चार द्वीप कुछ क्षेत्र लो टाइड और कुछ क्षेत्र हाई टाइड से तबाह हो सकता है।
- संयुक्त राष्ट्र ने भी चिंता जाहिर करते हुए कहा है कि बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप पर स्थानांतरित करने को लेकर शरणार्थियों को 'स्वतंत्र एवं सुविचारित निर्णय' लेने की अनुमति दी जानी चाहिए।

6. मानवाधिकार संगठनों का आरोप

- मानवाधिकार समूहों ह्यूमन राइट्स वॉच और एमनेस्टी इंटरनेशनल के मुताबिक कुछ शरणार्थियों को द्वीप पर जाने के लिए मजबूर किया गया है।

7. शरणार्थियों की रक्षा के लिये अंतर्राष्ट्रीय प्रावधान

- संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी संधि, 1951 का उद्देश्य शरणार्थियों की समस्याओं के प्रति आपात राहत पुनर्वास सहायता, सुरक्षा तथा स्थायी निदान उपलब्ध कराना है। जबकि शरणार्थियों की स्थिति पर प्रोटोकॉल, 1967 सभी देशों के शरणार्थियों को शामिल करता है।

8. भारत की शरणार्थी नीति

- भारत ने 1951 के शरणार्थी दर्जे के संबंध में संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी सम्मेलन समझौते पर या 'मेजबान राज्य' द्वारा आवश्यक रूप से शरणार्थियों को अधिकार और सेवाएँ देने से संबंधित प्रोटोकॉल पर अभी तक हस्ताक्षर नहीं किये हैं।

04 अप्रवासी भारतीयों को डाक मतपत्र की सुविधा प्रदान करने का प्रस्ताव

1. चर्चा का कारण

- हाल ही में चुनाव आयोग द्वारा अप्रवासी भारतीयों को डाक मतपत्रों (पोस्टल बैलट) के माध्यम से मतदान करने की इजाजत देने के लिए केंद्र सरकार के पास एक प्रस्ताव भेजा है।

2. रिपोर्ट के मुख्य बिंदु

- रिपोर्ट्स के अनुसार चुनाव आयोग अगले साल होने वाले असम, पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में विधानसभा चुनावों के लिए एनआरआई मतदाताओं को इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रेषित पोस्टल बैलट सिस्टम (ETPBS) का विस्तार करने के लिए तकनीकी रूप से और प्रशासनिक रूप से तैयार है। हालाँकि वर्तमान में विदेश में रहने वाले भारतीय मतदाता केवल अपने संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में अपना वोट डाल सकते हैं।
- रिपोर्ट्स के अनुसार अनुमानित एक करोड़ भारतीय हैं जो विदेशों में रहते हैं, इनमें से लगभग 60 लाख विदेशी मतदान के योग्य हो सकते हैं।
- वहीं प्रेषित पोस्टल बैलट सिस्टम वर्तमान में केवल सर्विस मतदाताओं के लिए उपलब्ध है। इस प्रणाली के तहत डाक मतपत्रों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजा जाता है और साधारण मेल के माध्यम से लौटाया जाता है।

3. संसद की अनुमति आवश्यक नहीं

- गौरतलब है कि विदेश में रह रहे अप्रवासी भारतीय मतदाताओं को सुविधा प्रदान करने के लिए सरकार को केवल कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961 में संशोधन करने की आवश्यकता है। इस कदम के लिए संसद की अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी।

4. क्रियान्वयन

- चुनाव आयोग के प्रस्ताव में कहा गया है कि पोस्टल बैलट के जरिए मतदान करने के इच्छुक किसी भी एनआरआई को चुनाव की सूचना के कम से कम पांच दिन बाद रिटर्निंग ऑफिसर (आरओ) को सूचित करना होगा।
- ध्यातव्य है कि चुनाव कि जानकारी मिलने के बाद आरओ इलेक्ट्रॉनिक रूप से बैलेट पेपर को भेज देगा।
- इसके बाद एनआरआई मतदाता मतपत्र पर अपनी वरीयता को अंकित करेगा और इसे उस देश के राजनयिक या काउंसुलर प्रतिनिधि के जरिए नियुक्त एक अधिकारी द्वारा घोषित घोषणा पत्र के साथ वापस भेज देगा, जहां का एनआरआई निवासी है।

5. आगे की राह

- यदि सरकार द्वारा चुनाव आयोग के इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो अगले साल होने वाले पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव में पोस्टल बैलट के जरिए एनआरआई वोट डाल सकते हैं।
- हालांकि मौजूदा प्रक्रिया में एनआरआई को अपने मतदान केंद्र पर ही मतदान किए जाने की सुविधा प्राप्त है।

05 भांग को सबसे हानिकारक ड्रग्स की सूची से हटाया गया

1. चर्चा का कारण

- हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मादक औषध आयोग (CND) द्वारा एकमात्र 'मादक औषध सम्मेलन' (Convention on Narcotic Drugs), 1961 की अनुसूची IV से भांग (Cannabis) और भांग की राल (Cannabis Resin) को हटाए जाने हेतु मतदान कराया गया और इस ऐतिहासिक मतदान के बाद भांग को खतरनाक ड्रग की सूची से हटा दिया गया। इस सिलसिले में हुई वोटिंग में 27 से ज्यादा देशों ने इसके पक्ष में वोट दिया।

2. पृष्ठभूमि

- भारत में भांग की खेती लगभग सात हजार वर्षों से होती आ रही है। इससे बनने वाले प्रोडक्ट्स से आयुर्वेद में कई बीमारियों का इलाज होता आया है।
- वहीं, अमेरिका के कैलिफोर्निया ने जनवरी 2018 में भांग को मंजूरी दी थी। अगले दो वर्षों में इसकी बिक्री से जो टैक्स मिला, वह लगभग 7,345 करोड़ रुपये था।
- ऐसा ही एक सुनहरा मौका भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई के पास भी आया था परन्तु मुंबई भांग-गांजा के जरिये 641 करोड़ रुपये का बड़ा राजस्व पाने से इसलिए चूक गई, क्योंकि भारत में इसे रखना, बिक्री और इस्तेमाल प्रतिबंधित है।

3. क्या होता है भांग का पौधा

- मारिजुआना धरती पर सबसे अधिक प्रचलित नशीला पदार्थ होता है। मारिजुआना (भांग-चरस- गांजा-हशीश) का दूसरा नाम कैनबिस भी है।
- यह कैनबिस सैटाइवा नाम के पौधे से प्राप्त होता है।
- उल्लेखनीय है कि भांग के पौधे के फूल, पत्तियों और तनों को सूखाकर बनने वाला गांजा सबसे ज्यादा प्रचलित है।

4. कैनबिस के प्रभाव

- कैनबिस के लगातार इस्तेमाल से तार्किक समझ और फैसले लेने में मुश्किल हो सकती है। साथ ही गंभीर स्वास्थ्य समस्याएँ उत्पन्न हो सकती हैं।
- इस बात का प्रमाण बढ़ रहा है कि जो लोग किसी गंभीर मानसिक बीमारी, अवसाद या मनोविकृति से ग्रसित होते हैं उनमें कैनबिस उपयोग की संभावना अधिक होती है या फिर अतीत में इन लोगों ने कैनबिस लंबी अवधि के लिए इस्तेमाल किया है।
- कैनबिस के सेवन से लोग अनेक शारीरिक व्याधियों के शिकार हो सकते हैं। वहीं हिंसा और गुनाह की प्रवृत्ति के चपेट में आने से स्वयं को तथा परिवार को संकट में डाल सकते हैं।

5. भारत की स्थिति

- भारत में मादक पदार्थों के संदर्भ में नारकोटिक ड्रग एवं सायकोट्रोपिक सब्सटेंस अधिनियम, 1985 (The Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985) बनाया गया था, जिसे प्रभावी बनाने के लिए 2014 में संशोधन बिल लाया गया।
- इसके आधार पर 2015 में नया कानून बनाया गया। यह एक्ट चरस, गांजा या फिर कैनबिस के दूसरे रूपों को पूरी तरह प्रतिबंधित करता है। हालांकि इस कानून में कैनबिस की परिभाषा में भांग को नहीं जोड़ा गया है।
- वर्तमान मतदान में भारत सहित अमेरिका और अधिकांश यूरोपीय राष्ट्रों ने भांग को 'सबसे हानिकारक ड्रग्स' की सूची से हटाने के पक्ष में मतदान किया।
- वहीं चीन, पाकिस्तान और रूस द्वारा प्रस्ताव के विरोध में मतदान किया गया।

6. आगे की राह

- सरकार को यह प्रयास करना चाहिए कि कैनबिस (भांग) का व्यावसायीकरण उस स्तर का ना हो सके जैसे अमेरिका में देखा जा रहा है। आज वहाँ कैनबिस को आइस्क्रीम सॉफ्ट ड्रिंक्स आदि रूपों में परोसा जा रहा है।
- भारत सरकार को चाहिए कि वह बच्चों, युवा या फिर वे लोग जो किसी प्रकार कैनबिस का प्रयोग कर रहे हैं उन्हें इसके गलत प्रभावों की जानकारी दे।
- सरकार को चाहिए कि वे उन लोगों को जो कैनबिस के आदि हो चुके हैं, उन्हें अच्छी स्वास्थ्य व सुविधा उपलब्ध करायें।
- भले ही सरकार इसे देश में वैधता ना दे लेकिन इस दिशा में जरूरी कदम उठाये और देखें कि क्या कैनबिस के प्रभाव सही मायने में अच्छे हैं या बुरे हैं।

06 हायाबुसा–2 अंतरिक्ष यान

1. चर्चा का कारण

- हाल ही में जापान का अन्तरिक्ष यान हायाबुसा-2 सुदूर अन्तरिक्ष में स्थित क्षुद्रग्रह से नमूने लेकर धरती पर लौटा है।

2. पृष्ठभूमि

- हायाबुसा-2 द्वारा लाये गये क्षुद्रग्रह के नमूने से सौर प्रणाली सहित पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति का पता लगाने में मदद मिल सकती है।
- यह अन्तरिक्ष यान क्षुद्रग्रह रयूगू से चट्टानों के नमूनों को धरती पर लेकर आया है। ये नमूने जिस कैप्सूल में रखा गया उसे अंतरिक्ष यान ने धरती से 2,20,000 किलोमीटर (1,36,700 मील) दूरी पर ही छोड़ दिया था, जोकि ऑस्ट्रेलिया के एक दूरस्थ, आबादी वाले क्षेत्र वूमेरा में जाकर गिरा।
- ध्यातव्य है कि हायाबुसा-2 ने पृथ्वी से करीब 30 करोड़ किलोमीटर दूर यात्रा करने के बाद रयूगू क्षुद्रग्रह से धूल के नमूने और प्राचीन सामग्री जमा की और अब यान छह साल के मिशन को पूरा करने के बाद धरती की तरफ लौटा है।
- हायाबूसा-2 के आधे सैंपल जेएएक्सए और अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा और अन्य अंतरराष्ट्रीय एजेंसी के बीच साझा किए जाएंगे. बाकी सैंपल को भविष्य के अध्ययन के लिए रख लिए जाएंगे। हायाबुसा-2 का काम अभी खत्म नहीं हुआ है और अब यह दो नए क्षुद्रग्रहों तक पहुंचने की यात्रा पर रवाना होगा।

3. हायाबुसा-2 अंतरिक्ष मिशन

- हायाबुसा-2 अंतरिक्ष मिशन जापानी अंतरिक्ष एजेंसी, JAXA द्वारा संचालित मिशन है।
- जापान ने इस अन्तरिक्ष यान को धरती के निकट स्थित एक क्षुद्रग्रह नमूना एकत्र कर उसे धरती पर वापस लाने के लिए भेजा था।
- इसे 3 दिसंबर 2014 को लॉन्च किया गया था और यह 27 जून 2018 को पृथ्वी के निकट स्थित क्षुद्रग्रह 162173 रायुगु की सतह पर उतरा था।
- रिमोट सेंसिंग, सैंपलिंग की सुविधाओं से युक्त हायाबुसा-2 चार छोटे रोवर्स को अपने साथ ले गया था। इस अन्तरिक्ष यान पर बड़े फ्रिज के आकार वाले सोलर पैनल लगाये गये थे।
- इस मिशन का उद्देश्य क्षुद्रग्रह अथवा एस्ट्रॉयड पर क्रेटर का निर्माण करके वहां से नमूने एकत्रित करके वर्ष 2020 के अंत तक पृथ्वी पर वापिस लौटना था।

5. हायाबुसा

- सितंबर 2005 के मध्य में, हायाबुसा क्षुद्रग्रह इटोकावा पर उतरा और क्षुद्रग्रह से नमूने एकत्र करने में कामयाब रहा। यह जून 2010 में नमूनों के साथ पृथ्वी पर लौट आया, साथ ही पृथ्वी पर क्षुद्रग्रह के नमूनों को लेकर लौटने वाला पहला अंतरिक्ष यान बन गया।

4. मिशन का महत्व

- वैज्ञानिकों का मानना है कि एस्टरॉयड सौरमंडल विकसित होने के शुरुआती समय में ही बन गए थे। क्षुद्रग्रह रायगु भी एक सी-टाइप क्षुद्रग्रह सौर प्रणाली के शुरुआती रयूगू काल का एक अवशेष-है। इसलिए रयूगू पर जैविक पदार्थ, पानी और जीवन की उत्पत्ति के लिए जरूरी तत्व भारी मात्रा में उपलब्ध हो सकते हैं।

07 थारू जनजाति की अनूठी संस्कृति

1. चर्चा का कारण

- हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने थारू जनजाति की अनूठी संस्कृति को दुनिया भर में फैलाने की योजना शुरू की है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य इन जनजातीय गांवों को पर्यटन के मानचित्र पर लाना है, जो कि जनजातियों के लिए रोजगार पैदा करेगा और जनजातीय आबादी वाले क्षेत्र में आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान करेगा।

2. मुख्य बिंदु

- यह एक होम स्टे योजना है जिसके तहत उत्तर प्रदेश वन विभाग पर्यटकों को लखीमपुर, पीलीभीत, बलरामपुर और बहराइच समेत राज्य के तमाम जंगलों में बसे थारू जनजातीय लोगों के प्राकृतिक आवास में रहने का अनुभव प्रदान करेगा।
- होम स्टे योजना के जरिये वन निगम जंगलों के बीच बसे थारू गांवों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के साथ-रोजगार से भी सीधे जोड़ेगा।
- जंगल के बीच बसे इन गांवों को बिना किसी निर्माण और तोड़ फोड़ के होम स्टे योजना से जोड़ा जाएगा। प्राकृतिक रूप से बने आवास और झोपड़ियों का इस्तेमाल ग्रामीणों की सहमति से सैलानियों के ठहरने के लिए किया जाएगा।
- वन निगम थारू समुदाय के लोगों को सैलानियों से बातचीत और बेहतर व्यवहार का प्रशिक्षण भी देगा। सुरक्षा और सफाई के साथ ही जंगल के नियम कानून सैलानियों को बताने का जिम्मा भी गांव के लोगों पर होगा।

3. योजना का लाभ

- जंगल के बीच अपने घरों में ठहरने और खाने की सुविधा देने के बदले में थारू गांव के लोग सैलानियों से अच्छी कीमत भी ले सकेंगे।
- हर साल देश विदेशों से जंगलों में आने वाले सैलानियों को थारू गांवों में रुकने और उनकी अनूठी संस्कृति से जुड़ने, समझने का अवसर भी मिलेगा।
- इस योजना के तहत घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों पर्यटकों की भागीदारी अपेक्षित है।
- सैलानियों के जरिये सरकार थारू जनजाति के रहन-सहन, खान-पान, पहनावे और संस्कृति का परिचय देश-दुनिया से कराएगी।

4. थारू जनजाति

- थारू शब्द का अर्थ है 'थेरवाद बौद्ध धर्म के अनुयायी'
- यह जनजाति शिवालिक या निचले हिमालय में स्थित तराई क्षेत्रों में रहते हैं।
- इनमें से ज्यादातर लोग कृषि सम्बन्धी कार्य करते हैं। थारू जनजातीय लोग नेपाल और भारत दोनों देशों में निवास करते हैं।
- भारत में थारू जनजाति से सम्बंधित लोग बिहार, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में रहते हैं।
- थारू जनजातीय लोग थारू भाषा बोलते हैं। नेपाल के थारू भोजपुरी भाषा के एक प्रकार का उपयोग करते हैं।
- थारू महिलाओं को अधिक संपत्ति का अधिकार प्रदान किये गये हैं।

5. सरकार द्वारा चलाई जा रही जनजातियों से संबंधित अन्य योजनायें

- उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में अनुसूचित जनजाति के विकास के लिए कम से कम 9 योजनाएं चलाई जा रही हैं।
- इसमें आश्रम पद्धति स्कूल, एकलव्य मॉडल स्कूल, स्कालरशिप योजना, अनुसूचित जनजाति उत्पीड़न योजना के तहत आर्थिक सहायता, अनुसूचित जनजाति की छात्राओं को मुफ्त साइकिल व ड्रेस योजना, अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं के लिए विवाह अनुदान योजना और सामूहिक विवाह योजना आदि शामिल है।

6. निष्कर्ष

- 2011 की जनगणना के अनुसार, उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजाति की संख्या 11,34,273 है। एक अनुमान के मुताबिक, पिछले 9 साल में इनकी संख्या 20 लाख के आकंड़े को पार कर गई है। इनमें सबसे बड़ी संख्या थारू समुदाय की है।
- यूपी सरकार का यह फैसला देश में जन जातीय समुदाय के विकास का नया रोड मैप साबित हो सकता है।

7 वस्तुनिष्ठ प्रश्न तथा उनके व्याख्या सहित उत्तर (ब्रेन बूस्टर्स पर आधारित)

01 हवाना सिंड्रोम

प्र. हवाना सिंड्रोम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. यह एक प्रकार का 'प्रत्यक्ष ऊर्जा हथियार' है।
2. सर्वप्रथम 2016 में क्यूबा में अमेरिका दूतावास के अधिकारियों में हवाना सिंड्रोम के लक्षण पाए गए थे।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 2 (b) केवल 1
(c) 1 और 2 दोनों (d) दोनों में से कोई नहीं

उत्तर: (c)

व्याख्या: इस बीमारी के कुछ लक्षणों में उल्टी, नाक से खून आना, थकान चक्कर आना, मानसिक परेशानी आदि शामिल है। अमेरिका की नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेस के अनुसार यह बीमारी संभवत: निर्दिष्ट माइक्रोवेव विकिरण के कारण होती है। इस संदर्भ में उपर्युक्त सभी कथन सही हैं। अत: उत्तर (c) होगा।

02 हम्पी के प्रतिष्ठित पत्थर निर्मित रथ

प्र. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. हम्पी की स्थापना 1336 ई. में हरिहर और बुक्का ने की थी।
2. हम्पी को यूनेस्को ने वर्ष 1986 में विश्व विरासत स्थल घोषित किया था।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा /से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 2 (b) केवल 1
(c) 1 और 2 दोनों (d) दोनों में से कोई नहीं

उत्तर: (c)

व्याख्या: हम्पी 1336 से 1556 (तालिकोटा के युद्ध) तक विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। यहां का हम्पी रथ वास्तुकला का एक अद्भुत नमूना है। यहां का विजय विठ्ठल मंदिर भी बहुत प्रसिद्ध है। हाल ही में इस मंदिर को छूने से रोकने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने सुरक्षात्मक बैरिकेड लगा दिया है। इस संदर्भ में उपर्युक्त सभी कथन सही हैं। अत: उत्तर (c) होगा।

03 रोहिंग्या शरणार्थियों का सुदूर द्वीप पर पुनर्वासन

प्र. रोहिंग्या शरणार्थियों का सुदूर द्वीप पर पुनर्वासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. म्यांमार राष्ट्रीयता कानून, 1982 के तहत म्यांमार ने रोहिंग्या आबादी को नागरिकता देने से इंकार कर दिया है।
2. वर्तमान समय में रोहिंग्या शरणार्थी बांग्लादेश के तटीय शहर 'कॉक्स बाजार' में शिविरों में रह रहे हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा /से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) दोनों में से कोई नहीं

उत्तर: (c)

व्याख्या: हाल ही में बांग्लादेश ने 1,600 से अधिक रोहिंग्या शरणार्थियों के पहले समूह को एक सुदूर द्वीप पर प्रतिस्थापित किया है। जिस द्वीप पर रोहिंग्या शरणार्थियों को प्रतिस्थापित किया जा रहा है उसका नाम भाषण चार द्वीप है। इस संदर्भ में उपर्युक्त सभी कथन सही हैं। अत: उत्तर (c) होगा।

04 प्रवासी भारतीयों को डाक मतपत्र की सुविधा प्रदान करने का प्रस्ताव

प्र. प्रवासी भारतीयों को डाक मतपत्र की सुविधा प्रदान करने का प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. चुनाव आयोग अगले साल होने वाले असम पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में विधान सभा चुनावों के लिए एनआरआई मतदाताओं को मताधिकार देने का प्रस्ताव दिया है।
2. एक अनुमान के अनुसार लगभग 1 करोड़ भारतीय विदेशों में रहते हैं, इनमें से लगभग 60 लाख विदेशी मतदान के योग्य हैं।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2

(c) न तो 1 न ही 2 (d) 1 और 2 दोनों

उत्तरः (d)

व्याख्याः हाल ही में चुनाव आयोग द्वारा अप्रवासी भारतीयों को डाक मतपत्रों (पोस्टल बैलट) के माध्यम से मतदान करने की इजाजत देने के लिए केन्द्र सरकार के पास एक प्रस्ताव भेजा है। इस संदर्भ में उपर्युक्त दोनों कथन सही हैं। अतः उत्तर (d) होगा।

05 भांग को सबसे हानिकारक ड्रग्स की सूची से हटाया गया

प्र. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. संयुक्त राष्ट्र मादक औषध आयोग (CDD) द्वारा भांग को खतरनाक ड्रग्स की सूची से हटा दिया गया है।
2. भारत में मादक पदार्थों के संदर्भ में नारकोटिक ड्रग्स एवं सायकोट्रोपिक सब्सटेंस अधिनियम, 1985 बनाया गया था।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 2 (b) केवल 1

(c) 1 और 2 दोनों (d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

उत्तरः(c)

व्याख्याः मारिजुआना (भांग-चरस-गांजा-हशीश) का दूसरा नाम कैनबिस भी है। यह सैटाइवा नामक पौधे से प्राप्त होता है। विदित हो कि भांग के पौधे के फूल, पत्तियों और तनों को सूखाकर बनने वाला गांजा सबसे ज्यादा प्रचलित है। इस संदर्भ में उपर्युक्त सभी कथन सही हैं। अतः उत्तर (c) होगा।

06 हायाबुसा-2 अंतरिक्ष यान

प्र. हायाबुसा-2 अंतरिक्ष यान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. हायाबुसा-2 अंतरिक्ष यान जापानी अंतरिक्ष एजेंसी जाक्सा (JAXA) द्वारा संचालित मिशन है।
2. हायाबुसा-2 अंतरिक्षयान रूसी अंतरिक्ष एजेंसी स्पेस-X द्वारा संचालित मिशन है।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों (d) इनमें से कोई नहीं

उत्तरः (a)

व्याख्याः हायाबुसा-2 को 3 दिसंबर 2014 को लॉन्च किया गया था और यह 2018 में पृथ्वी के निकट स्थित क्षुद्रग्रह 162173 र्युगू की सतह पर उतरा था। इस क्षुद्रग्रह पर हायाबुसा-2 चार छोटे रीवर्स को अपने साथ ले गया था। हायाबुसा-2 अंतरिक्ष यान का संबंध रूस से नहीं है अतः कथन 2 गलत है। इसलिए उत्तर (a) होगा।

07 थारू जनजाति की अनूठी संस्कृति

प्र. थारू जनजातियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. थारू जनजातियाँ मुख्यतः शिवालिक या निचले हिमालय में स्थित तराई क्षेत्रों में रहते हैं।
2. थारू जनजाती लोग थारू भाषा बोलते हैं।

उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों (d) इनमें से कोई नहीं

उत्तरः (c)

व्याख्या : हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने थारू जनजातियों के सुंदर संस्कृति को प्रोत्साहित करने के लिए 'होम स्टे' योजना शुरू की है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य जनजातीय गावों को पर्यटन के मानचित्र पर लाना है। इस संदर्भ में उपर्युक्त सभी कथन सही हैं। अतः उत्तर (c) होगा।

7 महत्वपूर्ण खबरें

01 भारत, अमेरिका की करेंसी मैनिपुलेटर देशों की निगरानी सूची में शामिल

चर्चा में क्यों?

- अमेरिकी ट्रेजरी (U.S. Treasury) विभाग ने स्विट्जरलैण्ड और वियतनाम को करेंसी के साथ छेड़छाड़ करने वाला देश बताया है और उन्हे 'करेंसी मैनिपुलेटर' की सूची में रखा है। इसके साथ ही भारत, ताइवान और थाइलैंड को भी निगरानी सूची (Monitoring List) में रखा गया है।

पृष्ठभूमि

- अमेरिकी का ट्रेजरी विभाग अंतरराष्ट्रीय आर्थिक और विनिमय दर नीति की समीक्षा रिपोर्ट के आधार पर करेंसी मेनिपुलेटर्स देशों की पहचान करता है।
- यूएस ट्रेजरी ने स्विटजरलैंड और वियतनाम द्वारा डॉलर के मुकाबले अपनी करेंसी का अवमूल्यन करने की आशंका के चलते, दोनों देशों को करेंसी मैनिपुलेटर की सूची में रखा है।
- अमेरिका के ट्रेजरी विभाग ने वियतनाम पर 'अनुचित प्रतिस्पर्धी लाभ' लेने का आरोप लगाया है।

करेंसी मैनिपुलेटर का क्या अर्थ है?

- अमेरिकी के ट्रेजरी विभाग द्वारा उन देशों को करेंसी मैनिपुलेटर कहा जाता है, जो "अनुचित मुद्रा प्रथाओं" को अपनाकर डॉलर के मुकाबले अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करते हैं।

क्या होता है अवमूल्यन (Devaluation) ?

- अर्थशास्त्र में अवमूल्यन का तात्पर्य अन्य मुद्राओं के संबंध में किसी एक मुद्रा के मूल्य में कमी करने से होता है। अवमूल्यन में किसी देश के द्वारा अन्य मुद्राओं या मुद्राओं के समूह के समतुल्य अपनी मुद्रा के मूल्य को कृत्रिम तरीके से कम कर दिया जाता है। उदाहरण के लिए यदि डॉलर की तुलना में रुपए का अवमूल्यन किया गया तो आपको डॉलर खरीदने के लिए अत्यधिक रुपए खर्च करने पड़ेंगे।

करेंसी मैनिपुलेटर देशों की पहचान के मापदंड

- उस देश का अमेरिका के साथ पिछले 12 माह के दौरान द्विपक्षीय व्यापार अधिशेष (trade surplus) कम से कम 20 अरब डॉलर का रहा हो,
- पिछले 12 माह के दौरान उस देश की जीडीपी का 2 फीसदी से ज्यादा चालू खाता अधिशेष रहा हो,
- 12 महीने की अवधि में उस देश की जीडीपी का 2 फीसदी से ज्यादा विदेशी मुद्रा की शुद्ध खरीद हो।

भारत को निगरानी सूची में रखने का कारण

- भारत का कई वर्षों से लगातार अमेरिका के साथ द्विपक्षीय माल व्यापार अधिशेष बना हुआ है, जो अब +20 बिलियन का आंकड़ा भी पार कर चुका है। जून 2020 के पहले की चार तिमाहियों में द्विपक्षीय माल व्यापार अधिशेष +22 बिलियन था।
- केंद्रीय बैंक के आंकड़ों के अनुसार, भारत की विदेशी मुद्रा की शुद्ध खरीद में 2019 की दूसरी छमाही में तेजी आई है। महामारी की शुरुआत के दौरान विदेशी मुद्रा की बिक्री के बाद, भारत ने 2020 की पहली छमाही के दौरान शुद्ध खरीद को बनाए रखा।

02 चीन और यूएई की चार कंपनियों को अमेरिका ने किया ब्लैक लिस्ट

चर्चा में क्यों?

- अमेरिका ने चीन और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) स्थित पेट्रोकेमिकल उत्पाद की चार कंपनियों को काली सूची में डाला है। ये कंपनियाँ ईरान से पेट्रोकेमिकल की खरीद कर रही थीं।
- अमेरिका के वित्त मंत्रालय के अनुसार जिन चार कंपनियों को काली सूची में डाला गया है वे ईरान की ट्रिलियंस पेट्रोकेमिकल कंपनी लिमिटेड से उत्पादों का आयात कर रही थीं। अमेरिकी प्रशासन ने जनवरी 2020 में ही ईरान की इस कंपनी पर प्रतिबंध लगा दिये थे।
- चीन और यूएई के अलावा वियतनाम की कंपनी वियतनाम गैस और केमिकल ट्रांसपोर्टेशन कॉर्पोरेशन पर भी ईरान से संबंध होने के कारण प्रतिबंध लगाए गए है।

ईरान पर लगे व्यापार प्रतिबंध की पृष्ठभूमि

- ईरान ने 2015 में अमरीका, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, रूस और जर्मनी के साथ एक परमाणु समझौता किया था, जिसके अनुसार ईरान को अपने परमाणु कार्यक्रमों को सीमित करना था और उसके बदले उस पर लगे संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक प्रतिबंध हटाए जाने थे।
- इसी समझौते के तहत हथियारों पर लगा प्रतिबंध अक्तूबर, 2018 में खत्म होना था। इससे ठीक पहले 2018 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस समझौते से अमेरिका को अलग कर लिया था।
- अमेरिका का कहना था की ईरान ने समझौते की शर्तों को पूरा नही किया है और यह समझौता अमेरिकी हितों की अनदेखी करता है।
- इसके बाद ईरान पर सुरक्षा परिषद द्वारा 2007 और 2010 में लगाए गए प्रतिबंध पुनः आरोपित कर दिये गए थे।
- इसके अलावा अमेरिका ने ईरान पर बैलिस्टिक मिसाइल और आतंकवाद को समर्थन देने का आरोप लगाते हुए ईरान के खिलाफ नये आर्थिक प्रतिबंधों की घोषणा की थी।

03 किसान रेल

चर्चा में क्यों?

- भारतीय रेलवे किसान रेल ट्रेनों (Kisan Rail trains) की संख्या बढ़ाने की योजना बना रही है।

पृष्ठभूमि

- सब्जियों और फलों को देश के विभिन्न हिस्सों में पहुँचने हेतु भारतीय रेलवे, किसान रेल ट्रेनों की संख्या बढ़ाने की योजना बना रही है ताकि किसानों को बेहतर दाम मिलें और फल व सब्जियों की बर्बादी को रोका जा सके।
- इसके लिए भारतीय रेलवे, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के साथ विचार-विमर्श कर रही है।
- वर्तमान में भारतीय रेलवे चार किसान रेल ट्रेनें चला रही है। ऐसी ट्रेनों को चलाने की राष्ट्रीय स्तर पर काफी अधिक मांग है क्योंकि किसानों को इससे लाभ मिल रहा है।
- भारतीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने हाल ही में कहा था कि सरकार कश्मीर से देश के विभिन्न हिस्सों में सेब के परिवहन के लिए 'किसान रेल गाड़ियों' की योजना बना रही है।
- उल्लेखनीय है की किसान रेल सेवाओं का उपयोग करते हुए किसानों को और मदद तथा प्रोत्साहन देने के लिए रेल मंत्रालय और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने अधिसूचित फलों और सब्जियों (खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय को-ऑपरेशन ग्रीन्स-'टॉप टू टोटल' योजना के तहत) की ढुलाई में 50 प्रतिशत सब्सिडी देने का निर्णय लिया है। यह सब्सिडी सीधे किसान रेल को प्रदान की जाएगी।

क्या है किसान रेल (Kisan Rail)?

- केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस साल के बजट में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) के आधार पर किसान रेल के संचालन की घोषणा की थी, ताकि फलों, सब्जियों, दूध आदि जैसे उत्पादों का त्वरित परिवहन सुनिश्चित किया जा सके।
- केन्द्रीय बजट 2020-21 में वित्त मंत्री ने जल्द खराब होने वाले उत्पादों जैसे दूध, मांस और मछली आदि के लिए निर्बाध नेशनल कोल्ड सप्लाई चेन बनाने की घोषणा की थी।
- वर्तमान में भारतीय रेलवे चार किसान रेल ट्रेनें चला रही है-

- पहली किसान रेल, देवलाली (नासिक, महाराष्ट्र) से दानापुर (पटना, बिहार) के बीच चली। इस रेल का उद्घाटन 07.08.2020 किया गया था। यह एक साप्ताहिक ट्रेन है। इसके बाद लोकप्रिय मांग के आधार पर इस ट्रेन को मुजफ्फरपुर (बिहार) तक बढ़ा दिया गया और इसका संचालन सप्ताह में दो बार कर दिया गया। देश की दूसरी और दक्षिण भारत की पहली किसान रेल-अनंतपुर (आंध्र प्रदेश) से आदर्श नगर दिल्ली तक चलती है। इसका उद्घाटन 09.09.2020 को किया गया था। यह एक साप्ताहिक ट्रेन है।
- तीसरी किसान रेल-बेंगलुरु (कर्नाटक) से हजरत निजामुद्दीन (दिल्ली) के बीच चलती है। इसका उद्घाटन 09.09.2020 को साप्ताहिक ट्रेन के रूप में किया गया।
- चौथा किसान रेल-नागपुर और वारुद ऑरेंज सिटी (महाराष्ट्र) से आदर्श नगर दिल्ली तक चलेगी। इसका उद्घाटन 14.10.2020 को किया गया है।

किसान रेल के लाभ

- किसान रेल का उद्देश्य किसानों की आय को दोगुना करने में मदद करना है।
- यह ट्रेन 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने के लक्ष्य को साकार करने की दिशा में एक कदम है।
- यह ट्रेन कम समय में सब्जियों, फलों जैसे जल्द खराब होने वाले कृषि उत्पादों को बाजार में लाने में मदद करेगी।
- फ्रोजन कंटेनरों वाली इस ट्रेन द्वारा जल्द खराब होने वाली खाद्य वस्तुओं जिसमें मछली, मांस और दूध शामिल है, के लिए एक निर्बाध नेशनल कोल्ड सप्लाई चेन बनाई जा सकेगी।

04 मानव विकास सूचकांक 2020

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) ने मानव विकास सूचकांक (HDI) जारी किया है, जिसमें भारत को 131वां स्थान प्राप्त हुआ है।

मानव विकास सूचकांक (Human Development Index- HDI) 2020 से जुड़े प्रमुख बिन्दु

1. भारत की स्थिति

- संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) द्वारा जारी किए गए वर्ष 2020 के मानव विकास सूचकांक (एचडीआई) में 189 देशों में भारत को 131वां स्थान प्राप्त हुआ है। भारत पिछले साल की अपेक्षाकृत दो पायदान नीचे खिसक गया है। जबकि भारत की वर्ष 2018 के मानव विकास सूचकांक में रैंक 130 थी।
- हालाँकि यूएनडीपी इंडिया के प्रतिनिधि का कहना है कि भारत की रैंकिंग में गिरावट का यह अर्थ नहीं कि "भारत ने अच्छा नहीं किया, बल्कि इसका अर्थ है कि अन्य देशों ने बेहतर किया।" उन्होंने भारत द्वारा कार्बन उत्सर्जन कम करने के प्रयासों की भी सराहना की है।
- वर्ष 2020 के मानव विकास सूचकांक (एचडीआई) की रिपोर्ट के अनुसार, क्रय शक्ति समता (पीपीपी) के आधार पर 2018 में भारत की प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय 6,829 अमेरिकी डॉलर थी जो 2019 में गिरकर 6,681 डॉलर हो गई है।
- इसके अतिरिक्त , इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि वर्ष 2019 में भारतीयों की जीवन प्रत्याशा 69.7 वर्ष थी। गौरतलब है कि इस सूचकांक के माध्यम से यूएनडीपी किसी राष्ट्र में स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन के स्तर का मापन करता है।
- वर्ष 2020 के मानव विकास सूचकांक (एचडीआई) की रिपोर्ट में भारत की एचडीआई वैल्यू 0.645 है।

2. अन्य देशों की स्थिति

- संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) द्वारा जारी किए गए वर्ष 2020 के मानव विकास सूचकांक (एचडीआई) में नॉर्वे सबसे ऊपर रहा और उसके बाद आयरलैंड, स्विट्जरलैंड, हांगकांग और आइसलैंड का स्थान है।
- वर्ष 2020 के मानव विकास सूचकांक (एचडीआई) में भारत के पड़ोसी देशों में भूटान 129वें स्थान पर, बांग्लादेश 133वें स्थान पर, नेपाल 142वें स्थान पर और पाकिस्तान 154वें स्थान पर रहा है।

3. नई मीट्रिक (New metric) का प्रयोग: प्लैनेटरी प्रेशर-एड्जस्टेड एचडीआई (Planetary Pressures-adjusted HDI,or PHDI)

- वर्ष 2020 में पहली बार संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) ने प्रत्येक देश के प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन (Per-Capita Carbon Emissions) और उसके मैटेरियल फुटप्रिंट (material footprint) के कारण होने वाले प्रभाव को दर्शाने के लिए एक नई मीट्रिक की शुरुआत की है। यह वस्तुओं को बनाने के लिए और सेवाओं का उपभोग करने के लिए उपयोग किए जाने वाले जीवाश्म ईंधन,

धातुओं और अन्य संसाधनों की मात्रा को मापता है।

- यूएनडीपी इंडिया के प्रतिनिधि का कहना है कि यह मानव प्रगति का कम आकर्षक, लेकिन स्पष्ट मूल्यांकन है।
- यूएनडीपी के मुताबिक अगर इस नई मीट्रिक (new metric) को शामिल करते हुए भारत की स्थिति देखी जाएगी तो भारत वर्ष 2020 के मानव विकास सूचकांक (एचडीआई) में 8 पायदान ऊपर पहुँच जाएगा।
- इस नई मीट्रिक (new metric) को शामिल करते हुए प्लैनेटरी प्रेशर-एड्जस्टेड एचडीआई या पीएचडीआई (Planetary Pressures-adjusted HDI, or PHDI) नाम दिया गया है।

क्या है मानव विकास सूचकांक (Human Development Index-HDI)?

- मानव विकास सूचकांक को प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम(यूएनडीपी) द्वारा जारी किया जाता है।
- इस सूचकांक में अभी तक विभिन्न देशों की स्थिति निम्नलिखित तीन प्रमुख बुनियादी आयामों पर आकलित की जाती थी-
  1. जीवन प्रत्याशा
  2. ज्ञान तक पहुँच
  3. प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय
- उल्लेखनीय है कि मानव विकास सूचकांक की अवधारणा का विकास पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब-उल-हक द्वारा किया गया था। इस अवधारणा का बाद में नब्बे के दशक में भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन द्वारा समर्थन किया गया।
- तत्पश्चात संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) ने इस अवधारणा को अपनाया तथा पहला मानव विकास सूचकांक वर्ष 1990 में जारी किया गया।

05 कच्छ का हाइब्रिड अक्षय ऊर्जा पार्क

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुजरात में कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं में दुनिया का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा पार्क भी शामिल है। इसके साथ उन्होंने अलवणीकरण संयंत्र, स्वचालित दुध प्रसंस्करण और पैकेजिंग संयंत्र सहित कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी।

कच्छ का हाइब्रिड अक्षय ऊर्जा पार्क (Hybrid Renewable Energy Park)

- गुजरात के कच्छ जिले में भारत-पाकिस्तान सीमा के पास खावड़ा गांव में बनने वाला यह अक्षय ऊर्जा पार्क दुनिया में अपनी तरह का सबसे बड़ा पार्क है, जिसकी उत्पादन क्षमता 30 GW होगी। यह हाइब्रिड अक्षय ऊर्जा पार्क अंतर्राष्ट्रीय सीमा से मात्र 6 किमी की दूरी पर स्थित होगा।
- यह परियोजना भारत सरकार के वर्ष 2022 तक 175 GW अक्षय ऊर्जा क्षमता स्थापित करने के दृष्टिकोण के अनुरूप है।
- यह अक्षय ऊर्जा पार्क 72, 600 हेक्टेयर भूमि पर बनाया जाएगा, जिसमें 49,600 हेक्टेयर भूमि पर हाइब्रिड पार्क जोन होगा, जिसमें 24,800 मेगावाट क्षमता के पवन तथा सौर ऊर्जा संयंत्र होंगे तथा दूसरा 23,000 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला एक विशेष पवन ऊर्जा क्षेत्र होगा।
- इस हाइब्रिड अक्षय ऊर्जा पार्क क्षेत्र में निम्नलिखित विद्युत उत्पादन कंपनियों के प्लांट लगेंगे:
- अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (19,000 हेक्टेयर; 9,500 मेगावाट)
- सरजन रियलिटीज लिमिटेड (सुजलॉन, 9,500 हेक्टेयर; 4,750 मेगावाट)
- एनटीपीसी लिमिटेड (9,500 हेक्टेयर; 4,750 मेगावाट)
- गुजरात इंडस्ट्रीज पावर कंपनी लिमिटेड (4,750 हेक्टेयर; 2,375 मेगावाट)
- गुजरात राज्य विद्युत निगम (6,650 हेक्टेयर; 3,325 मेगावाट)।
- 72, 600 हेक्टेयर भूमि पर बनने वाले इस पार्क के अंतर्गत विशेष पवन पार्क क्षेत्र के लिए आरक्षित संपूर्ण 23,000 हेक्टेयर भूमि सौर ऊर्जा निगम (SECI) को आवंटित की गई है।

क्या होती है हाइब्रिड अक्षय ऊर्जा (Hybrid Renewable Energy)?

- हाइब्रिड अक्षय ऊर्जा या हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा (Hybrid Renewable Energy) में एक से अधिक अक्षय ऊर्जा उत्पादन स्रोतों को एक दूसरे के साथ एकीकृत किया जाता है, जैसे कि सौर और पवन ऊर्जा। हाइब्रिड अक्षय ऊर्जा (Hybrid Renewable Energy) तकनीक अक्षय ऊर्जा के विश्वसनीय, सस्ती और ऊर्जा के वितरण हेतु एक एकीकृत समाधान प्रस्तुत

करते हैं। हाइब्रिड अक्षय ऊर्जा या हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा की तकनीक सौर और पवन ऊर्जा के संयोजन से या पवन और जल ऊर्जा के संयोजन से अक्षय ऊर्जा सिस्टम ग्रिड को स्थिरता प्रदान करते हैं।

क्या होते हैं हाइब्रिड अक्षय ऊर्जा पार्क (Hybrid Renewable Energy Park)?

- हाइब्रिड अक्षय ऊर्जा पार्क निम्न मानकों के सन्दर्भ में इष्टतम समाधान प्रदान करते हैं–
  1. ट्रांसमिशन की कम लागत
  2. फर्म के प्रेषण-सक्षम शक्ति में सुधार
  3. संसाधन पूर्वानुमान की त्रुटियां को कम करना
  4. कम CUF (Capacity Utilisation Factor)
  5. मांग के अनुसार पावर की शेड्यूलिंग।

भारत में नवीकरणीय ऊर्जा की स्थिति

- भारत सरकार ने 2022 के अंत तक 175 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य निर्धारित किया है, जिसमें 60 गीगावाट पवन ऊर्जा से, 100 गीगावाट सौर ऊर्जा से, 10 गीगावाट बायोमास ऊर्जा से एवं पाँच गीगावाट लघु पनबिजली से, नवीकरणीय ऊर्जा को संस्थापित करने का लक्ष्य रखा है।
- इसमें सौर ऊर्जा से 100 गीगावॉट बिजली उत्पादन का लक्ष्य शामिल है। वर्तमान में भारत के सौर ऊर्जा उत्पादन में सर्वाधिक योगदान रूफटॉप सौर ऊर्जा (40%) और सोलर पार्क (40%) का है।
- सौर ऊर्जा से उत्पादित बिजली देश में बिजली उत्पादन की स्थापित क्षमता का 16% है। सरकार का लक्ष्य इसे बढ़ाकर स्थापित क्षमता का 60% करना है। इसके अलावा वर्ष 2035 तक देश में सौर ऊर्जा की मांग 7 गुना तक बढ़ने की संभावना है।
- भारत में पवन ऊर्जा की कुल स्थापित उत्पादन क्षमता 35,129 मेगावाट है। वर्ष 2022 तक अपतटीय पवन ऊर्जा से 5 गीगावाट और 2030 तक 30 गीगावाट का लक्ष्य घोषित किया गया है।
- 2014 तक देश की नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन क्षमता 34,000 मेगावाट थी, जो सितंबर 2019 में बढ़कर 82,580 मेगावाट हो गई है और 31,150 मेगावाट की क्षमता स्थापित करने के लिये प्रयास विभिन्न चरणों में है।

06 हरित भवन

चर्चा में क्यों?

- हैदराबाद में 12वें एकीकृत आवास के लिए ग्रीन रेटिंग (Green Rating for Integrated Habitat Assessment- GRIHA) शिखर सम्मेलन के उद्घाटन के दौरान उपराष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडू ने वित्त आयोगों और स्थानीय निकायों से कर राहत प्रोत्साहन सहित विभिन्न उपायों के माध्यम से हरित भवन (Green Building) निर्माण को प्रोत्साहित करने की अपील की।
- श्री नायडू ने कहा कि, हरित इमारतों को एकल खिड़की मंजूरी प्रदान करने के लिए सभी राज्यों के द्वारा ऑनलाइन पोर्टल बनाए जाने चाहिए।
- उल्लेखनीय है कि 7.61 अरब वर्ग फुट ग्रीन बिल्डिंग फुटप्रिंट के साथ भारत दुनिया के शीर्ष 5 देशों में शामिल है।

क्या होते हैं हरित भवन (Green Building)?

- हरित भवन एक ऐसा भवन होता है, जो अपने डिजाइन, निर्माण या संचालन में जलवायु संबंधी नकारात्मक प्रभावों को कम या समाप्त करते हुए हमारे जलवायु और प्राकृतिक वातावरण पर सकारात्मक प्रभाव पैदा करता है। हरित भवन बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में सहायक होते हैं और हमारे जीवन स्तर में सुधार लाते हैं।
- निम्नलिखित प्रमुख विशेषताएँ किसी भवन को हरित भवन बनाती हैं:
  1. ऊर्जा, जल और अन्य संसाधनों का कुशल उपयोग
  2. अक्षय ऊर्जा का उपयोग
  3. प्रदूषण और अपशिष्ट में कमी के उपाय के साथ पुन: उपयोग और पुनर्चक्रण को सक्षम करना
  4. अच्छी आंतरिक पर्यावरणीय वायु गुणवत्ता
  5. गैर-हानिकारक, नैतिक और पर्यावरण अनुकूल सतत भवन निर्माण सामग्री का उपयोग
  6. डिजाइन, निर्माण और संचालन का पर्यावरणीय दृष्टिकोण
  7. डिजाइन, निर्माण और संचालन द्वारा भवनों में रहने वालों के जीवन की गुणवत्ता पर विचार
  8. परिवेश में अनुकूलन को सक्षम बनाने वाली भवन निर्माण शैली
- कोई भी भवन हरित भवन हो सकता है, चाहे वह एक घर, कार्यालय, स्कूल, अस्पताल, सामुदायिक केंद्र या किसी अन्य प्रकार की संरचना हो, बशर्ते इसमें उपर्युक्त सूचीबद्ध विशेषताएं शामिल हों।

हरित भवनों के लाभ

- दुनिया भर में, इसके लाभों को देखते हुये हरित भवनों को बढ़ावा दिया जा रहा है। ये जलवायु परिवर्तन, स्थायी और संपन्न समुदायों का निर्माण और आर्थिक विकास को संबोधित करने वाले वैश्विक लक्ष्यों की श्रृंखला को प्राप्त करने में गति प्रदान करते हैं।

- हरित भवनों के लाभ को तीन श्रेणियों पर्यावरण, आर्थिक और सामाजिक में वर्गीकृत किया जा सकता है:

1. पर्यावरणीय लाभ

- हरित भवनों का सकारात्मक प्रभाव जलवायु और प्राकृतिक वातावरण पर होता है। हरित भवन कम जल, ऊर्जा या प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके न केवल पर्यावरण पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभावों को कम या समाप्त करते हैं, बल्कि वे कई मामलों में स्वयं से ऊर्जा और जैव विविधता को बढ़ाकर, पर्यावरण (भवन या शहर के पैमाने पर) पर सकारात्मक प्रभाव भी डालते हैं।
- संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी) के अनुसार भवन निर्माण क्षेत्र अन्य प्रमुख उत्सर्जन क्षेत्रों की की तुलना में ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में उल्लेखनीय रूप से कमी लाने की क्षमता रखता है। हरित भवनों को अपनाकर 2050 तक 84 गीगाटन कार्बन डाईऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करने की क्षमता प्राप्त की जा सकती है।
- यूएनईपी के अनुसार भवन निर्माण क्षेत्र में 2050 तक 50% या उससे अधिक की ऊर्जा बचत करने की क्षमता है, जो वैश्विक तापमान को पूर्व-औद्योगिक स्तरों से 2 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने में अत्यधिक महत्वपूर्ण है।
- ऑस्ट्रेलिया में ग्रीन स्टार प्रमाणन प्राप्त करने वाली हरित इमारते अन्य ऑस्ट्रेलियाई इमारतों की तुलना में औसतन 62% कम ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन करती है, और पीने योग्य पानी का 51% तक कम उपयोग करती है।
- भारतीय ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल (IGBC) द्वारा प्रमाणित हरित इमारते भारत में पारंपरिक इमारतों की तुलना में 40 - 50% की ऊर्जा बचत और 20 - 30% पानी की बचत करती हैं।
- दक्षिण अफ्रीका में ग्रीन स्टार प्रमाणन प्राप्त करने वाली हरित इमारते हर साल औसतन 30 - 40% ऊर्जा और उद्योग के मानदंडों की तुलना में हर साल 20 - 30% पीने योग्य पानी की बचत करती है।
- वहीं अमेरिका और अन्य देशों में LEED प्रमाणीकरण प्राप्त करने वाली हरित इमारतों

को गैर-हरी इमारतों की तुलना में 25 प्रतिशत कम ऊर्जा और 11 प्रतिशत कम पानी की आवश्यकता होती है।

2. आर्थिक लाभ

- यूरोपीय आयोग के अनुसार वैश्विक ऊर्जा दक्षता उपायों को अपनाकर ऊर्जा खर्च में 280 से 410 बिलियन तक की बचत हो सकती है।
- कनाडा की ग्रीन बिल्डिंग इंडस्ट्री ने जीडीपी में +23.45 बिलियन का उत्पादन किया और 300,000 से ज्यादा पूर्णकालिक रोजगार प्रदान किए हैं।
- यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के अनुसार अमेरिका में ग्रीन बिल्डिंग ने 2018 तक 3.3 मिलियन से अधिक नौकरियों सृजन किया था।
- हरित भवन क्षेत्र रोजगार सृजन के साथ-साथ सस्ती भवन निर्माण सामाग्री की उपलब्धता के लिए अभी महत्वपूर्ण है।

3. सामाजिक लाभ

- हरित भवन आर्थिक और पर्यावरण लाभ के अलावा सकारात्मक सामाजिक प्रभाव भी उत्पन्न करते हैं।
- हरित भवन में रहने वाले लोगों या कार्यालयों में काम वाले लोगों को स्वास्थ्य लाभों के रूप में प्राप्त होता हैं।
- हरे, अच्छी तरह से हवादार कार्यालयों में काम करने वाले लोगो के संज्ञानात्मक स्कोर (मस्तिष्क की कार्य क्षमता) में 101 प्रतिशत तक वृद्धि हो जाती है।
- शोध बताता है कि बेहतर इनडोर वायु गुणवत्ता (सीओ 2 और प्रदूषकों की कम सांद्रता, और उच्च वेंटिलेशन दर) मनुष्य के कार्य करने के सन्दर्भ में 8 प्रतिशत तक प्रदर्शन में सुधार ला सकती है।

भारत में हरित भवन को बढ़ावा देने वाली कुछ प्रमुख पहल

- स्मार्ट सिटीज मिशन जिसका लक्ष्य उन शहरों के विकास को बढ़ावा देना है जो मुख्य शहरी आधारभूत संरचना प्रदान करें और अपने नागरिकों को एक स्वच्छ और टिकाऊ वातावरण प्रदान करें।
- ब्यूरो ऑफ एनर्जी द्वारा एफिशिएंसी एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड (ईसीबीसी) का कार्यान्वयन
- ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चौलेंज इंडिया (जीएचटीसी-इंडिया) का आयोजन, जिसका उद्देश्य सर्वोत्तम उपलब्ध और सही निर्माण तकनीकों की पहचान करना और मुख्यधारा बनाना है, जो आवास निर्माण में प्रतिमान बदलाव को सक्षम करने के लिए टिकाऊ, हरित और आपदा-प्रतिरोधी हैं।
- अफोर्डेबल सस्टेनेबल हाउसिंग एक्सेलेरेटर्स - इंडिया (आशा- इंडिया) पहल के माध्यम से, संसाधन-कुशल, लचीला और टिकाऊ निर्माण के लिए नवीन सामग्रियों, प्रक्रियाओं और प्रौद्योगिकी की पहचान के लिए पांच इन्क्यूबेशन केंद्र स्थापित किए गए हैं।

क्लाइमेट-स्मार्ट सिटीज असेसमेंट फ्रेमवर्क (सीएससीएएफ) 2.0

- **हरित भवन पहल:** अधिक ऊर्जा दक्ष तथा इको अनुकूल भवनों के निर्माण के लिये न्यू एंड रिन्युवेबल एनर्जी मिनिस्ट्री ने द एनर्जी एंड रिसोर्स इन्स्टीट्यूट (टेरी) के सहयोग से भारत में हरित भवनों की रेटिंग हेतु राष्ट्रीय रेटिंग प्रणाली "ग्रीन रेटिंग फार इंटीग्रेटेड हेबिटेट असेसमेंट (गृह) विकसित की है।
- **हरित रेटिंग परियोजना:** यह सेंटर फार सायंस एंड एन्वायरन्मेंट (सीएसई) द्वारा भारतीय उद्योगों के अपना पर्यावरण संबंधी कार्यनिष्पादन सुधारने के लिये मार्गदर्शन प्रदान करने हेतु 1995 में आरंभ एक गैर सरकारी पहल है।
- **स्मेरा हरित रेटिंग्स:** भारत में उद्यमों की हरित रेटिंग एसएमईरेटिंग एजेंसी लि. (स्मेरा) द्वारा की जाती है। हरित रेटिंग सिडबी तथा स्मेरा की संयुक्त पहल है।
- सीआईआई द्वारा 'इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल' के माध्यम से ग्रीन बिल्डिंग मूवमेंट की पहल।

07 नीलगिरि बायोस्फीयर रिजर्व में टिड्डी की प्रजातियों का आकलन

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में नीलगिरि बायोस्फीयर रिजर्व में टिड्डी की प्रजातियों (Grosshopper Species) का आकलन करने का फैसला किया गया है।

टिड्डी की प्रजातियों (Grosshopper Species) के आकलन से संबंधित तथ्य

- टिड्डी (Grosshopper), पारिस्थितिकी तंत्र में जैव-विविधता (Biodiversity) का एक अनिवार्य हिस्सा होती है तथा यह एक संकेतक प्रजाति (Indicator Species) भी होती है।
- हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (International Union for Conservation of Nature-IUCN) के प्रजाति उत्तरजीविता आयोग (Species Survival Commission -SSC) ने दक्षिण भारत में नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में टिड्डी की प्रजातियों (Grosshopper Species) का अपनी तरह का पहला रेड-लिस्ट आकलन (Red List Assessment) करने का फैसला किया है, जिसका देश के अन्य हिस्सों में भी अनुसरण किया जायेगा।
- प्रजाति उत्तरजीविता आयोग द्वारा इस परियोजना की शुरुआत नीलगिरि बायोस्फीयर रिजर्व से तीन राज्यों केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में की जाएगी; यह टिड्डे के पारिस्थितिकी तंत्र (Grasshoppers Ecosystem) की स्थिति को समझने में मदद करेगा।
- नीलगिरि बायोस्फीयर रिजर्व में यह मूल्यांकन परियोजना (Assessment Project) वर्ष 2021 में शुरू की जाएगी और दो साल में पूरी होगी।
- यह परियोजना संयुक्त अरब अमीरात स्थित मोहम्मद बिन जायद प्रजाति संरक्षण कोष (Mohammad Bin Zayed Species Conservation Fund) द्वारा वित्त पोषित है, जो दुनिया भर में विभिन्न प्रजातियों के संरक्षण के लिए काम करता है।

टिड्डी (Grosshopper) के बारे में

- टिड्डी (Grosshopper), घास के मैदानों में वनस्पति को खाने वाले प्रमुख कीट (insect) हैं।
- ये मुख्यत: उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाये जाते हैं।
- पारिस्थितिक तंत्र में अन्य जानवरों के लिए शिकार और पोषक चक्र (Nutrient Cycling) में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है।

भारत में टिड्डों की चार प्रजातियां पाई जाती हैं-

1. मरूस्थली टिड्डे (शिस्टोसेरका ग्रीजिया)
2. प्रवासी टिड्डी (टिड्डा माइग्रेटोरिया)
3. बॉम्बे टिड्डे
4. ट्री टिड्डी (एनाक्रिडियम एसपी)।

- समय-समय पर भारतीय उपमहाद्वीप में इन टिड्डी दल का आक्रमण होता रहता है। टिड्डों की प्रजाति में रेगिस्तानी टिड्डों को सबसे खतरनाक और विनाशकारी माना जाता है।

प्रजाति उत्तरजीविता आयोग (Species Survival Commission-SSC) के बारे में

- IUCN की प्रजाति उत्तरजीविता आयोग (SSC) दुनिया के लगभग हर देश में फैले 9,000 से अधिक स्वयंसेवी विशेषज्ञों का एक विज्ञान-आधारित नेटवर्क है, जो सभी एक साथ मिलकर काम करते हैं।
- IUCN के वैश्विक प्रजाति कार्यक्रम के साथ निकट सहयोगी के रूप में कार्य करते हुए प्रजाति उत्तरजीविता आयोग (SSC) का प्रमुख कार्य जैव विविधता संरक्षण, प्रजातियों के निहित मूल्य, पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य और कार्यप्रणाली में उनकी भूमिका, पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के प्रावधान और मानव आजीविका के लिए उनके समर्थन के बारे में IUCN को जानकारी प्रदान करना है। इस जानकारी को संकटग्रस्त प्रजातियों की IUCN रेड लिस्ट में फीड किया जाता है।
- प्रजाति उत्तरजीविता आयोग (SSC) द्वारा अपने सदस्य संरक्षण संगठनों, सरकारी एजेंसियों और अन्य IUCN सदस्यों को वैज्ञानिक सलाह प्रदान किया जाता हैं। इसके साथ ही यह बहुपक्षीय पर्यावरणीय समझौतों के कार्यान्वयन का समर्थन करते हैं।
- प्रजाति उत्तरजीविता आयोग (SSC) द्वारा निर्मित नीतियां, दिशानिर्देश और मानक विभिन्न विशेष संरक्षण परियोजनाओं और पहलों को मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। उदाहरण जानवरों/प्रजातियों को पुन: उनके प्राकृतिक वातावरण में स्थापित करना, जब्त किए गए नमूनों को संभालना और आक्रामक प्रजातियों के प्रसार को रोकना।

अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (IUCN) के बारे में

- अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (The International Union For Conservation Of Nature-IUCN) दुनिया की प्राकृतिक स्थिति को संरक्षित रखने के लिये एक वैश्विक प्राधिकरण है, जिसकी स्थापना वर्ष 1948 में की गई थी।
- आईयूसीएन सरकारों तथा नागरिक समाज दोनों से मिलकर बना एक संघ है। इसका मुख्यालय स्विटजरलैंड में स्थित है।
- अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (IUCN) का घोषित लक्ष्य, विश्व की सबसे विकट पर्यावरण और विकास संबंधी चुनौतियों के लिए व्यावहारिक समाधान खोजने में सहायता करना है।
- अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (IUCN) विश्व के विभिन्न संरक्षण संगठनों के नेटवर्क से प्राप्त जानकारी के आधार पर लाल सूची(रेड लिस्ट) प्रकाशित करता है, जो विश्व में सबसे अधिक संकटग्रस्त प्रजातियों को दर्शाती है।

नीलगिरि बायोस्फीयर रिजर्व (Nilgiri Biosphere Reserve) के बारे में

- नीलगिरि बायोस्फीयर रिजर्व, भारत में वर्ष 1986 में स्थापित प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व है। यह पश्चिमी घाट (Western Ghats) में स्थित है और इसमें भारत के 10 जैव-भौगोलिक प्रांतों (Biogeographical Provinces) में से 2 शामिल हैं।
- नीलगिरि बायोस्फीयर रिजर्व मालाबार वर्षा वन (Malabar Rain Forest) के बायोग्राफिकल क्षेत्र (Biogeographic Region) के अंतर्गत आता है। मुदुमलाई वन्यजीव अभयारण्य, वायनाड वन्यजीव अभयारण्य, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान और मौन घाटी (Silent Valley) इस संरक्षित क्षेत्र के भीतर मौजूद हैं।

7 महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न (मुख्य परीक्षा हेतु)

03

05

07

01 क्या आप इस बात से सहमत हैं कि सभी धर्मों के लिए तलाक, भरण-पोषण एवं गुजारा भत्ता हेतु एक समान दिशा-निर्देश की आवश्यकता है? चर्चा कीजिए।

02 बांग्लादेश की मुक्ति संग्राम में भारत की भूमिका की चर्चा कीजिए।

03 हाल ही में एम्स के वैज्ञानिकों ने आंध्रप्रदेश में एकत्रित किए गए दूध के नमूनों में सीसे के अंश पाये हैं। इस संदर्भ में सीसा विषाक्तता को स्पष्ट करते हुए इसे नियंत्रित करने के उपाय सुझाएं।

04 हाल ही में मानव विकास सूचकांक में एक नई माप 'भूमंडलीय दबाव समायोजित मानव विकास सूचकांक' को शामिल किया गया है। भूमंडलीय दबाव समायोजित मानव विकास सूचकांक (Planetary Pressure adjusted. HDI) क्या है, तथा इसके शामिल करने के क्या निहितार्थ हैं?

05 "करंसी मैन्युपुलेटर्स" की अवधारणा क्या है? यह किस प्रकार वैश्विक वित्तीय बाजारों में किसी देश के प्रति विश्वास में कमी लाता है? परीक्षण कीजिए।

06 यौन अपराधों के खिलाफ महाराष्ट्र के प्रस्तावित कानूनों की आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

07 'समीक्षा याचिका' की अवधारणा स्पष्ट करते हुए इसके लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का उल्लेख करें।

7 महत्वपूर्ण तथ्य
(प्रारंभिक परीक्षा हेतु)

02

04

06

01 किस देश के प्रधानमंत्री को भारत के गणतंत्र दिवस (2021) के समारोह का मुख्य अतिथि चुना गया है?

ब्रिटेन (बोरीस जॉनसॉन)

02 किस व्यक्ति को 2020 का सामाजिक उद्यमी पुरस्कार के लिए श्वाब फांउडेशन ऑफ सोशल इंटरप्रयनोरशीप द्वारा चुना गया है?

अशरफ पटेल

03 किन देशों को 2030 और 2034 के एशियाई गेम्स के मेजबानी के लिए चुना गया है?

कतर (2030), सउदी अरब (2034)

04 किस शहर में संयुक्त राष्ट्र के 26वें जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (CoP26) का आयोजन किया जाएगा?

ग्लासगो (ब्रिटेन)

05 "The Presidential Years", जिसे हाल ही में खबरों में देखा गया, किस भारतीय राष्ट्रपति का संस्मरण है?

प्रणब मुखर्जी

06 हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने किस शहर में मुद्रा नोटों की प्राप्ति, भंडारण और वितरण के लिए एक स्वचालित बैंक प्रसंस्करण केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है?

जयपुर

07 किस राज्य ने "भूमि अतिक्रमण निषेध अधिनियम 2020" पारित किया है?

गुजरात

7 महत्वपूर्ण उक्तियाँ (निबंध तथा उत्तर लेखन में उपयोगी)

02

04
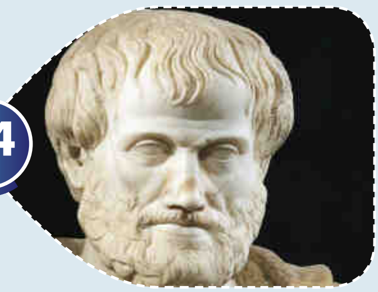

06

01 यदि आप सभी गलतियों के लिए दरवाजे बंद कर देंगे तो सच बाहर रह जायेगा।

रवीन्द्रनाथ ठाकुर

02 आपको मानवता में विश्वास नहीं खोना चाहिए। मानवता सागर के समान है; यदि सागर की कुछ बूँदें गन्दी हैं, तो पूरा सागर गंदा नहीं हो जाता।

महात्मा गांधी

03 शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसका उपयोग आप दुनिया को बदलने के लिए कर सकते हैं।

नेल्सन मंडेला

04 अच्छा व्यवहार सभी गुणों का सार है।

अरस्तु

05 अन्धकार कभी भी अन्धकार को दूर नहीं कर सकता। केवल प्रकाश ही अन्धकार को दूर कर सकता है। इसी प्रकार नफरत से नफरत दूर नहीं होती। केवल प्रेम ही नफरत को दूर कर सकता है।

मार्टिन लूथर किंग

06 चिंतन करो, चिंता नहीं, नए विचारों को जन्म दो।

स्वामी विवेकानंद

07 कुछ करने की इच्छा वाले व्यक्ति के लिए इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है।

अब्राहम लिंकन

ध्येयIAS®
most trusted since 2003

AN INTRODUCTION

Dhyeya IAS, a decade old institution, was founded by Mr. Vinay Singh and Mr. Q.H. Khan. Ever since its emergence it has unparallel track record of success. Today, it stands tall among the reputed institutes providing coaching for Civil Services Examination (CSE). The institute has been very successful in making potential realize their dreams which is evidents from success stories of the previous years.

Quite a large number of students desirous of building a career fro themselves are absolutely less equipped for the fairly tough competitive tests they have to appear in. Several others, who have a brilliant academic career, do not know that competitive exams are vartly different from academic examination and call for a systematic and scientifically planned guidance by a team of experts. Here one single move my invariably put one ahead of many others who lag behind. Dhyeya IAS is manned with qualified & experienced faculties besides especially designed study material that helps the students in achieving the desired goal.

Civil Services Exam requires knowledge base of specified subjects. These subjects though taught in schools and colleges are not necessarily oriented towards the exam approach. Coaching classes at Dhyeya IAS are different from classes conducted in schools and colleges with respect to their orientation. Classes are targeted towards the particular exam. classroom guidance at Dhyeya IAS is about improving the individuals capacity to focus, learn and innovate as we are comfortably aware of the fact that you can't teach a person anything you can only help him find it within himself.

DSDL Prepare yourself from distance

Distance learning Programme, DSDL, primarily caters the need for those who are unable to come to metros fro economic or family reason but have ardent desire to become a civil servant. Simultaneously, it also suits to the need of working professionals, who are unable to join regular classes due to increase in work load or places of their posting. The principal characteristic of our distance learning is that the student does not need to be present in a classroom in order to participate in the instruction. It aims to create and provide access to learning when the source of information and the learners are separated by time and distance. Realizing the difficulties faced by aspirants of distant areas, especially working candidates, in making use of the institute's classroom guidance programme, distance learning system is being provided in General Studies.The distance learning material is comprehensive, concise and examoriented in nature. Its aim is to make available almost all the relevant material on a subject at one place. Materials on all topics of General Studies have been prepared in such a way that, not even a single point will be missing. In other words, you will get all points, which are otherwise to be taken from 6-10 books available in the market / library. That means, DSDL study material is undoubtedly the most comprehensive and that will definitely give you added advantage in your Preliminary as well as Main Examination. These materials are not available in any book store or library. These materials have been prepared exclusively for the use of our students. We believe in our quality and commitment towards making these notes indispensable for any student preparing for Civil Services Examination. We adhere all pillars of Distance education.

Face to Face Centres

DELHI (MUKHERJEE NAGAR) : 011-49274400 | 9205274741, **DELHI (RAJENDRA NAGAR)** : 011-41251555 | 9205274743, **DELHI (LAXMI NAGAR)** : 011-43012556 | 9205212500, **ALLAHABAD** : 0532-2260189 | 8853467068, **LUCKNOW (ALIGANJ)** 9506256789 | 7570009014, **LUCKNOW (GOMTI NAGAR)** 7234000501 | 7234000502, **GREATER NOIDA RESIDENTIAL ACADEMY** : 9205336037 | 9205336038, **BHUBANESWAR** : 8599071555, **SRINAGAR (J&K)** : 9205962002 | 9988085811

Live Streaming Centres

BIHAR: PATNA – 6204373873, 9334100961 | **CHANDIGARH** – 9216776076, 8591818500 | **DELHI & NCR** : FARIDABAD – 9711394350, 1294054621 | **GUJARAT**: AHMEDABAD - 9879113469 | **HARYANA**: HISAR – 9996887708, 9991887708, KURUKSHETRA – 8950728524, 8607221300 | **MADHYA PRADESH**: GWALIOR -9993135886, 9893481642, JABALPUR- 8982082023, 8982082030, REWA –9926207755, 7662408099 | **MAHARASHTRA**: MUMBAI - 9324012585 | **PUNJAB**: PATIALA - 9041030070, LUDHIANA – 9876218943, 9888178344 | **RAJASTHAN**: JODHPUR - 9928965998 | **UTTARAKHAND**: HALDWANI-7060172525 | **UTTAR PRADESH**: ALIGARH – 9837877879, 9412175550, AZAMGARH - 7617077051, BAHRAICH - 7275758422, BAREILLY - 9917500098, GORAKHPUR - 7080847474, 7704884118, KANPUR - 7275613962, LUCKNOW (ALAMBAGH) - 7518573333,7518373333, MORADABAD - 9927622221, VARANASI - 7408098888

YouTube dhyeyaias | dhyeyaias.com | /dhyeya1 | STUDENT PORTAL

TRUEWORD
Quest for Wisdom

Price ₹ 40

Dhyeya IAS Now on Telegram

Join Dhyeya IAS Telegram Channel from link the given below

https://t.me/dhyeya_ias_study_material

नोट : पहले अपने फ़ोन में टेलीग्राम App Play Store से Install कर ले उसके बाद लिंक में क्लिक करें जिससे सीधे आप हमारे चैनल में पहुँच जायेंगे।

You can also join Telegram Channel through our website

www.dhyeyaias.com

www.dhyeyaias.com/hindi

ध्येयIAS
most trusted since 2003

Address: 635, Ground Floor, Main Road, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi 110009
Phone No: 011-47354625/ 26 , 9205274741/42, 011-49274400

Subscribe Dhyeya IAS Email Newsletter (ध्येय IAS ई-मेल न्यूजलेटर सब्सक्राइब करें)

जो विद्यार्थी ध्येय IAS के व्हाट्सएप ग्रुप (Whatsapp Group) से जुड़े हुये हैं और उनको दैनिक अध्ययन सामग्री प्राप्त होने में समस्या हो रही है | तो आप हमारेईमेल लिंक Subscribe कर ले इससे आपको प्रतिदिन अध्ययन सामग्री का लिंक मेल में प्राप्त होता रहेगा | **ईमेल से Subscribe करने के बाद मेल में प्राप्त लिंक को क्लिक करके पुष्टि (Verify) जरूर करें अन्यथा आपको प्रतिदिन मेल में अध्ययन सामग्री प्राप्त नहीं होगी |**

नोट (Note): अगर आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में अध्ययन सामग्री प्राप्त करनी है, तो आपको दोनों में अपनी ईमेल से Subscribe करना पड़ेगा | आप दोनों माध्यम के लिए एक ही ईमेल से जुड़ सकते हैं |

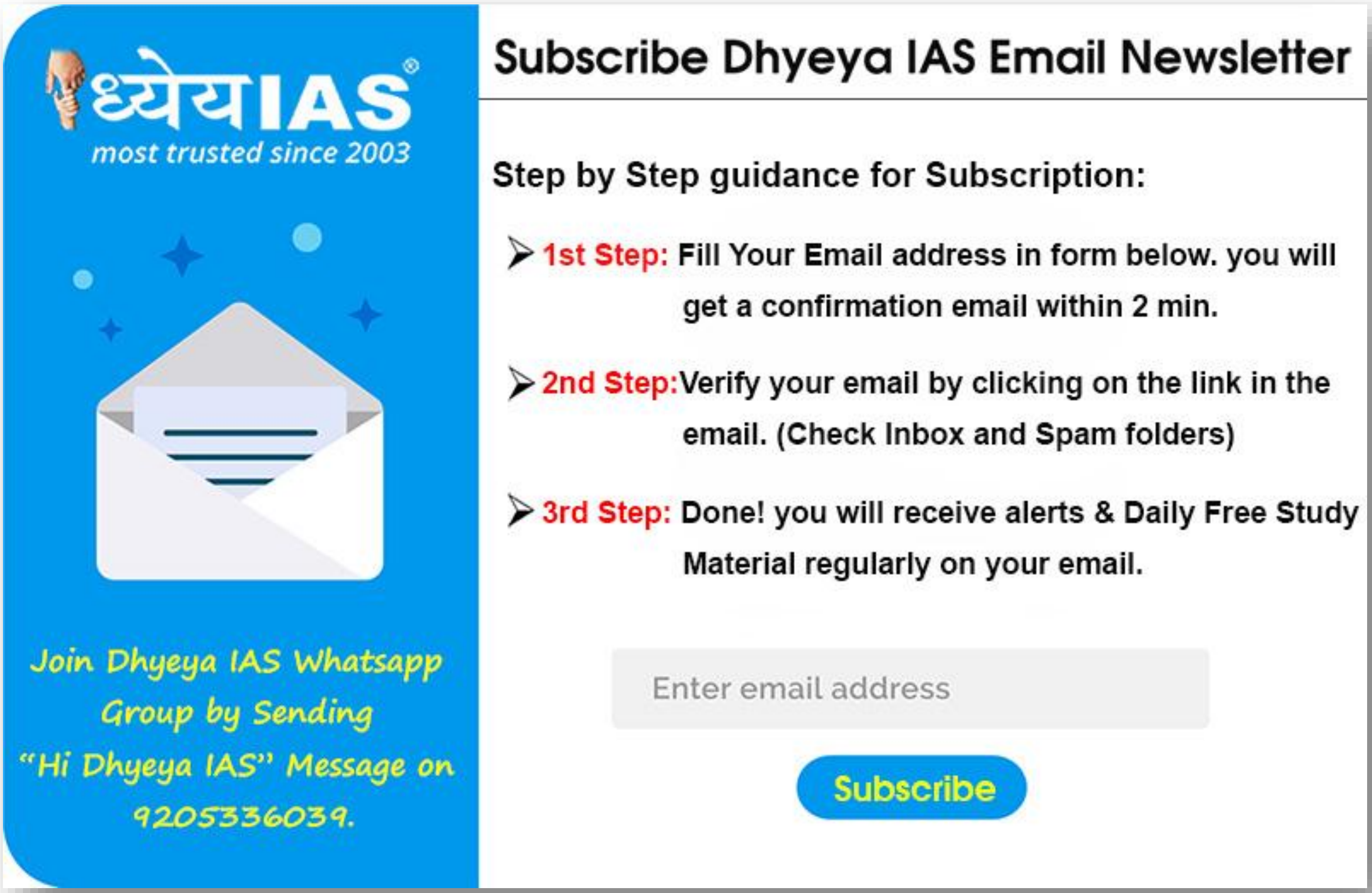

ध्येयIAS most trusted since 2003

Address: 635, Ground Floor, Main Road, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi 110009
Phone No: 011-47354625/ 26 , 9205274741/42, 011-49274400

ध्येयIAS®
most trusted since 2003

ADMISSIONS OPEN

FOR NEW ONLINE BATCH

IAS PRE-CUM-MAINS

PCS

OPTIONAL

HINDI & ENGLISH MEDIUM

Call: 9205962002 9506256789 | Whatsapp: 9205274741 | Visit: dhyeyaias.com